



31 AUG 2019

**GENERAL STUDIES (Module – 8)**निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVf/19 (N-M)-M-GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250Name: VIUESH

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): HindiReg. Number: Awake-19/F11Center & Date: M. Ngr. 30 Aug 19UPSC Roll No. (If allotted): 0877016**प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश**

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501, 8448485517

खंड - क/ SECTION - A

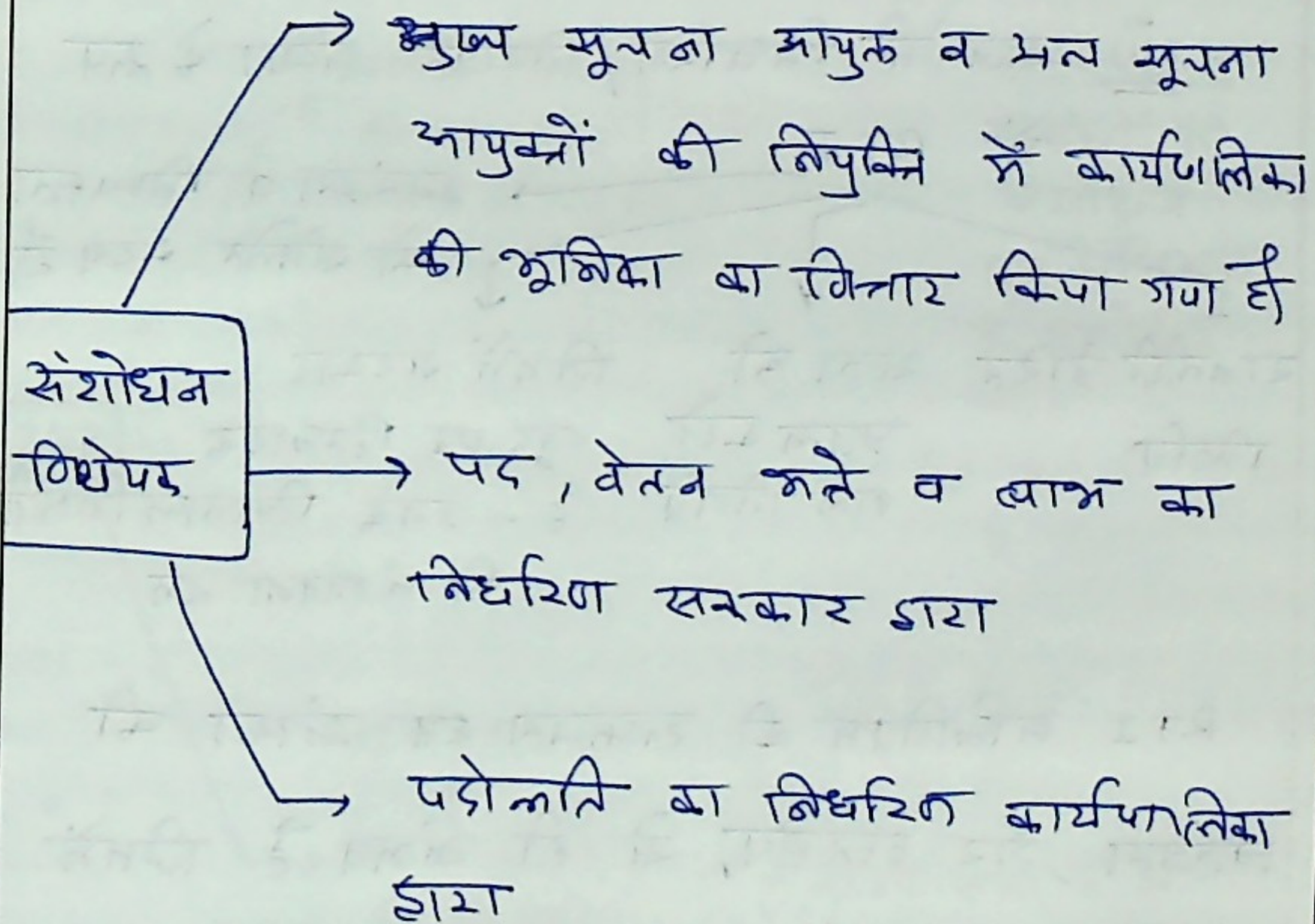
उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

संशोधन विधेयक की अनुच्छेद 19 के तहत
'जानने के अधिकार' को मूलाधिकार के रूप
में मान्यता को विधायी रूप देने के लिए
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लागू किया



पारदर्शी शासन पर प्रभाव

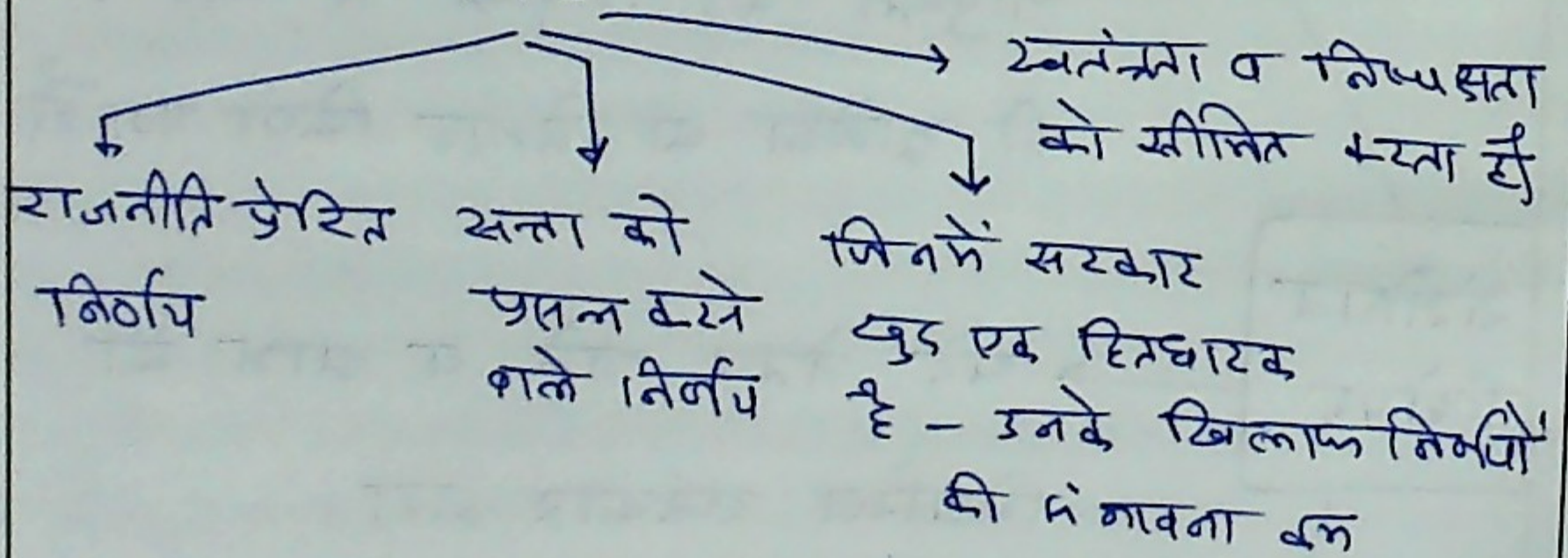
(i) दिवों का प्रकार

सूचना आयुक्त कार्यालय को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की आवश्यकता है।



कार्यपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका व सूचना आयुक्तों में दिवों का प्रकार उत्पन्न करेगा

(ii) राजनीति निर्धारण / नियंत्रित संस्था के रूप में RTI



RTI अधिनियम की सफलता इस संस्था की स्वतंत्रता, और हस्तक्षेप, से ही संभव है जिनमें कार्यपालिका की भूमिका सीमित होना ही बेहतर विकल्प है।

उम्मीदवार को
हाथिये में नोट
चाहिये।
(Candidate n
write on this

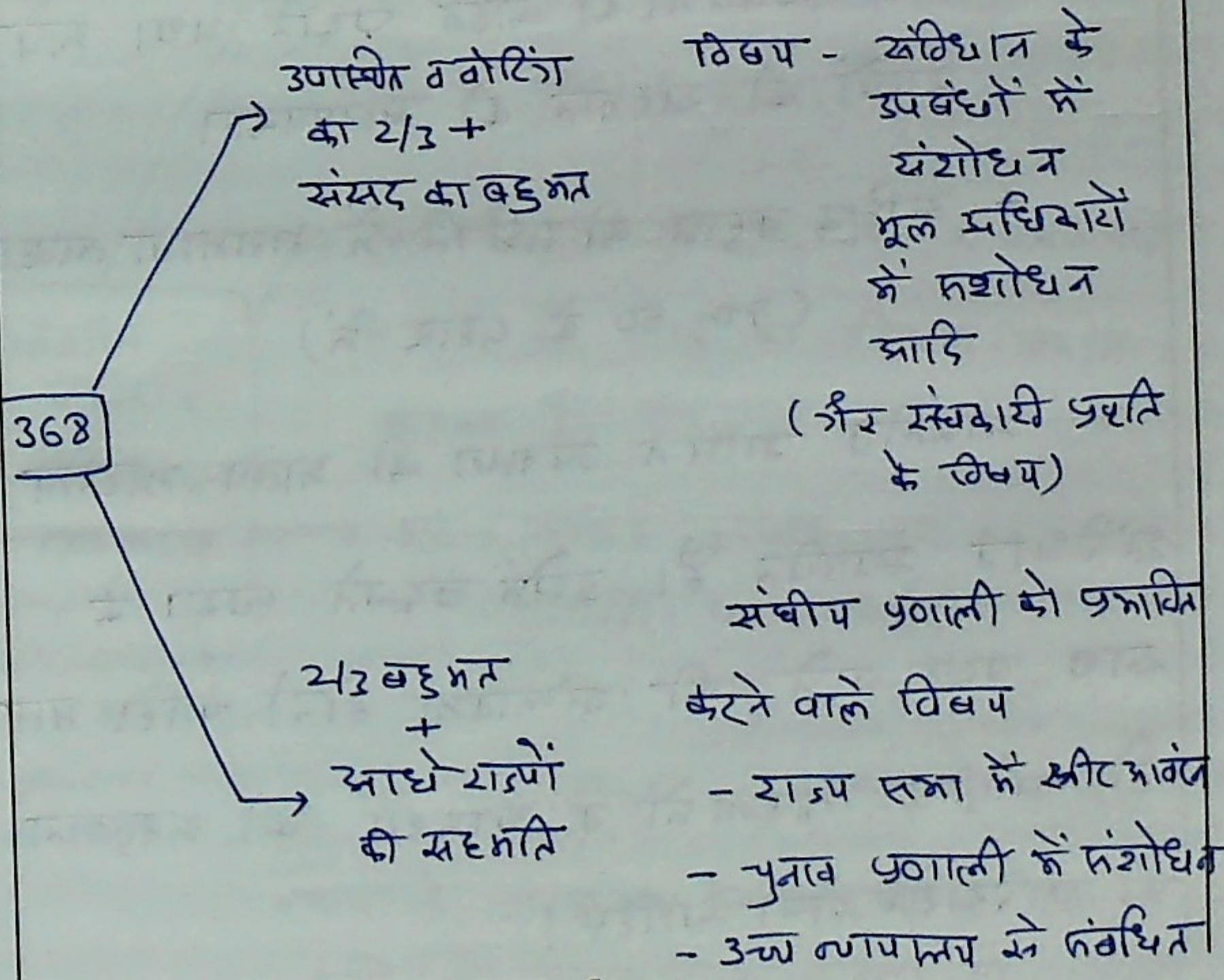
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारतीय संविधान को अमल में लाने का शक्तिशाली कहा जाता है। यह इसकी संशोधन की विभिन्न प्रणालियों की विशेषता के कारण कहा जाता है। विशेष परिस्थितियों (राज्य पुनर्गठन, राज नाम परिवर्तन) में ~~अमल~~ साधारण बहुमत के अलावा 368 से संविधान संशोधन की दो प्रणालियाँ



संशोधन प्रतिज्ञा की अलोचना क्यों?

* राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति पूर्णतया बंट
के पाल होने के कारण - राज्यों द्वारा
अलोचना

* राज्य सभा व लोक सभा दोनों से उत्तर
पाल होने की अनिवार्यता (संयुक्त बैठक का प्रयोग
नहीं)

- राज्य सभा में बहुमत ना होने पर आपात
अवस्था द्वारा अलोचना

* कई संशोधनों की कठिन प्रकृति तथा आधे
राज्यों की सहमति की आवश्यकता

* अधिक बहुमत की तभीति में मतभंगना व्यवहार
(70-80 के दशक में)

भारतीय शासन व्यवस्था की प्राक्का भारतीय
संशोधन स्थापित है। इसे बदलने स्वरूप के
साथ बदल जाने की संभावना होनी चाहिए साथ
ही मौलिक भावनाओं व आदर्शों की अक्षुण्णता
की परिरक्षित होनी चाहिए।

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

न्यायपालिका में न्याय के रूप में

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. एन भगवती

ने जनहित याचिका की शुरुवात की। यह

व्यापक स्तर पर उन्माहित लोगों को व्याप

दिताने का साधन बना।

जनहित
याचिका की
आवश्यकता
तथा महत्व

→ व्यापक रूप से उन्माहित लोगों की
सांख्यिक आवाज बनता है

→ सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच न रहने वाले
वक्तों की व्याप का विवक्ष्य प्रदान
करता है।

→ उदा. मुख्यई फुटपाथ पर रहने वाले
जालियों पर बिर्षण
LCRT अनुदान पर बिर्षण

→ यह सामाजिक राजनीति व आर्थिक
व्याप के उन्मादना के आदर्श को स्थापित
करने में महत्वपूर्ण बनता है

लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जनहित
याचिकाओं की संख्या इसके उद्देश्य को धुंधला
करती है-

- * जनहित याचिका कई बार व्यक्ति विशेष के
लाभ से उद्योित होती हैं
- * कभी कभी यह व्यक्तिगत, राजनीतिक महत्वाकांक्षी
प्रेरित भी हो सकती हैं।
- * जनहित याचिका को निर्धारित करने की
कोई वस्तुनिष्ठ मानक या सिद्धान्तों की
अनुपस्थिति है।
- * यह न्यायपालिका के क्षेत्र को बढ़ती है जिसका
प्रभाव सामान्य न्याय तंत्र पर पड़ता है।
सर्वे लिए न्याय भारतीय संविधान का आदर्श
है जिसमें जनहित याचिका एक प्रातिष्ठित धारा है।
शर्त यह है कि इसका लक्ष्य जनहित हो। हाल ही
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका हेतु नियम
की विस्तारियों को रद्द करेगा।

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10
- Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

भारत ने ब्रिटिश वेमब्लिटर मॉडल को अपनाया

जिसे कार्यपालिका (अस्थायी)

को विधायिका से चुना

जाता है। कार्यपालिका

पर नियंत्रण हेतु

विधायिका

राजनीतिक कार्यपालिका

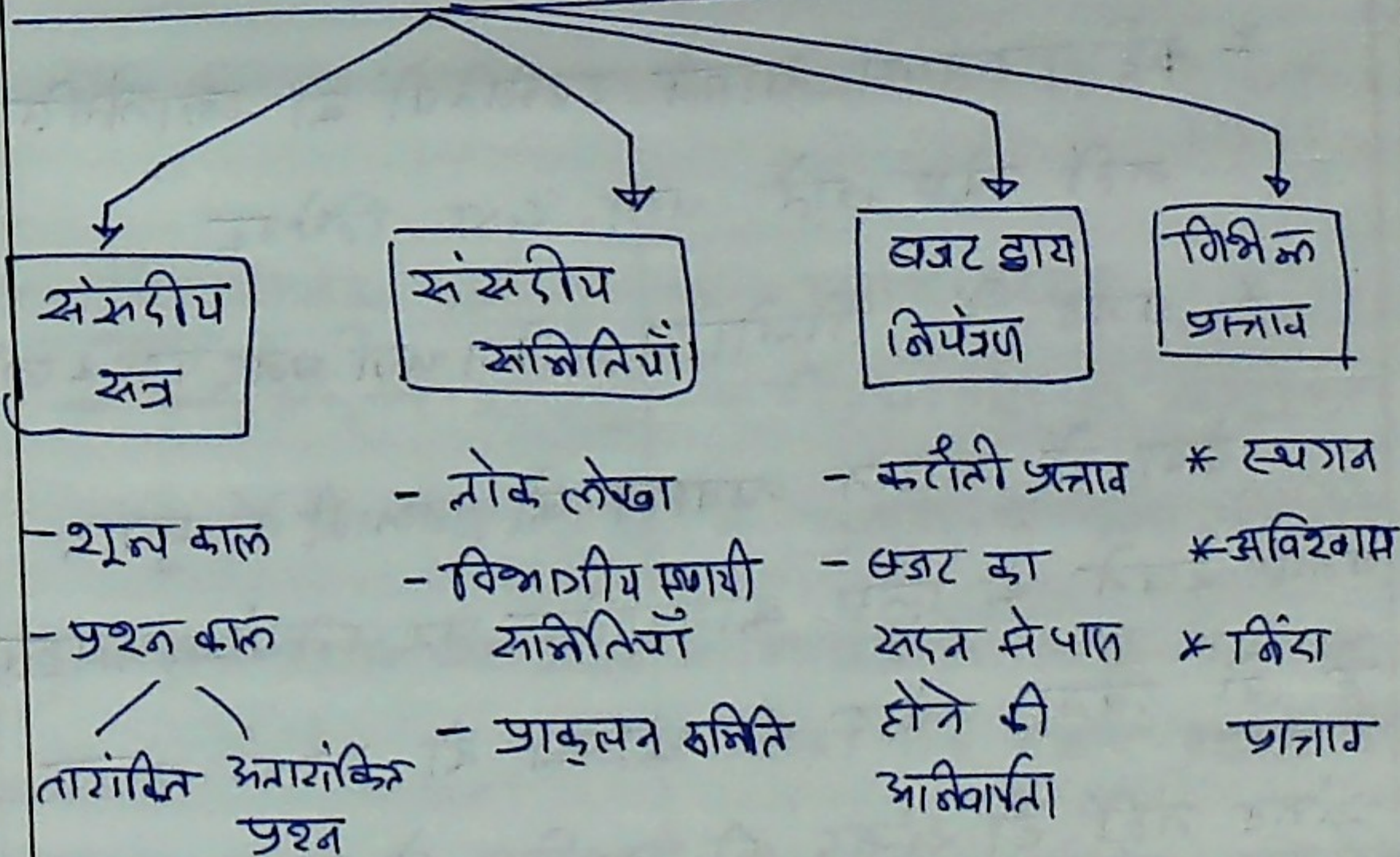
स्थायी कार्य
(नैकशाही)

कार्यपालिका

पर्यप्त व्यवस्था की गई है जो संसद के माध्यम

से सुनिश्चित होती है

कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण



कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की सीमाएँ

* नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था संसद है जिसे

* बैठकों की घंटी (पिछले वर्ष केवल 65) संख्या होती है।

* बार बार स्थान

* तारिक चर्चा की कमी

की समझाएँ देखने को मिलती है।

* विभागीय स्थायी समितियों व बजट से जुड़ी समितियों पर कार्य का अति स्वतंत्र + राजनीति प्रेरित चरनाएँ

* कई महत्वपूर्ण मामले समितियों को स्थानांतरित नहीं किए जाते यथा GST विधेयक

* बजट में गैलोरिज (बिना चर्चा बजट पार & ला)

देश में शासन व्यवस्था को प्रभावी व सुचारु बनाए रखने के लिए कार्यपालिका पर नियंत्रण आवश्यक है जो बिना संसद की भूमिका को प्रभावी बनाए रखने नहीं है। संसद की प्रभाविता को बढ़ाया जा सकता है।

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दबाव समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

राजनीतिक दल एक समूह है जो निरिच्छ
उद्देश्यों, आदर्शों, घोषणाओं के साथ चुनाव प्रक्रिया
में भाग लेता है। यह बहुत ज़ादर कर शक्त
ज़ादर कर ज़ाधिकारों का प्रयोग करता है यथा
कांग्रेस, बीजेपी, वसपा यादि

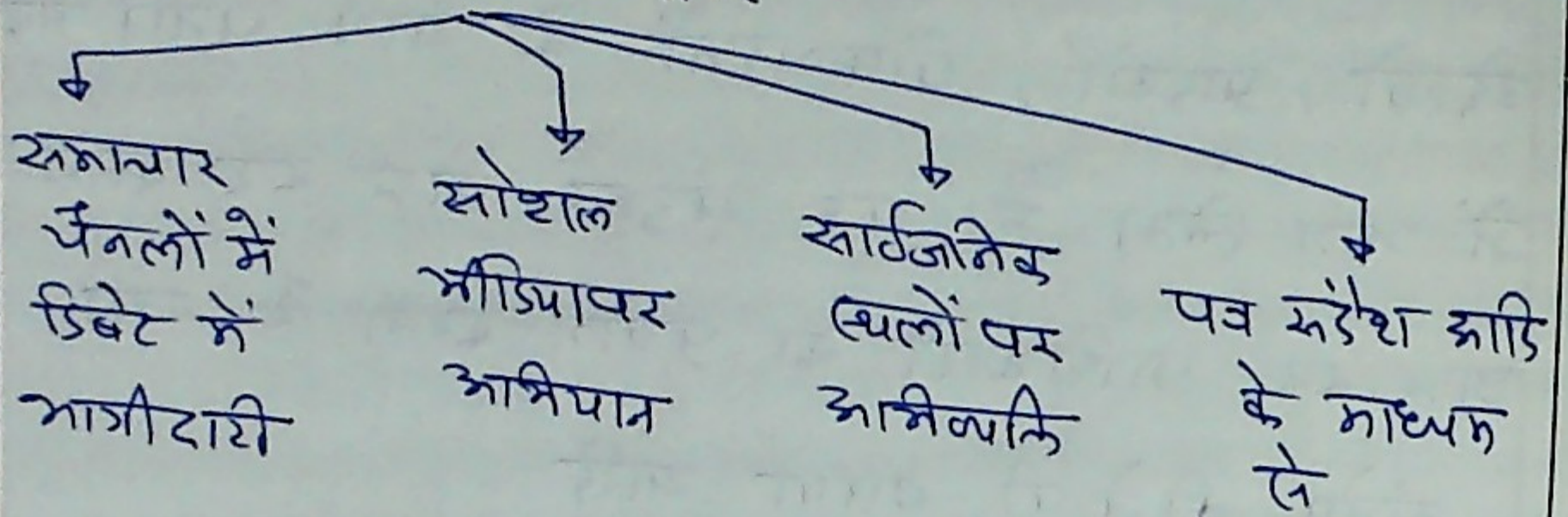
दबाव समूह हितधारकों का ऐसा समूह है
जो बिना प्रत्यक्ष रूप से शक्त में भाग लिख लना
को अपने हित में निर्णय हेतु संभावनाएँ जुटाता है।

उदा कृषक - राष्ट्रीय कृषक संघ विद्यार्थी - ABVP
NSUI

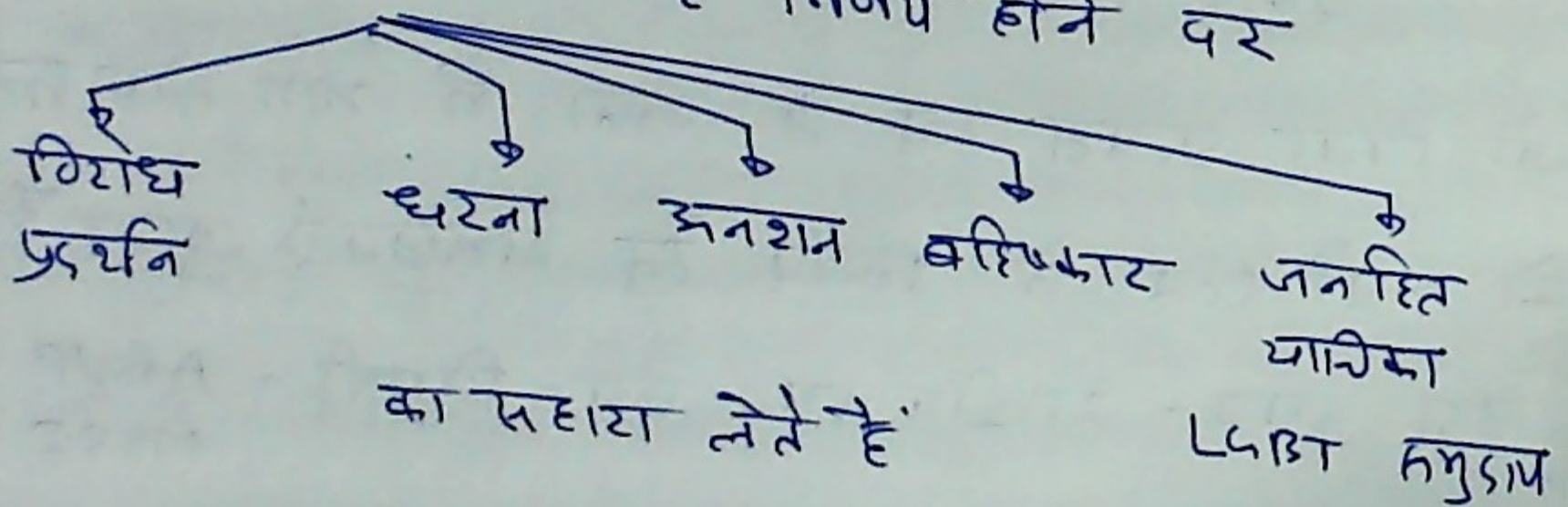
राजनीतिक दल	दबाव समूह
* प्रतिनिधियों का समूह	* हितधारकों का समूह
* चुनावों में भाग लेते हैं	* चुनावों में भाग नहीं लेते
* बहुत ज़ादर ज़ादर पर ज़ादर करते हैं।	* शासन में भाग ना लेकर शक्त पर दबाव ज़ालते हैं।
* शक्त में उत्पन्न ज़ागीदारी	* उत्पन्न: शामिल नहीं होते।

दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके

* समूह की मान्यता को सरकार तक पहुँचाने है। इसके लिए



* हितों के विरुद्ध निर्णय लेने पर



* अपनी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को सलाह, प्रशिक्षण, नीति निर्माण में शामिल करने का उपाय करते हैं।

दबाव समूह सरकार व जनता के बीच की सही समझना को सुवैधानिक तरीकों पर जागरूक बनाने के साथ-साथ उत्तरदायी बनाने का प्रयास करते हैं।

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

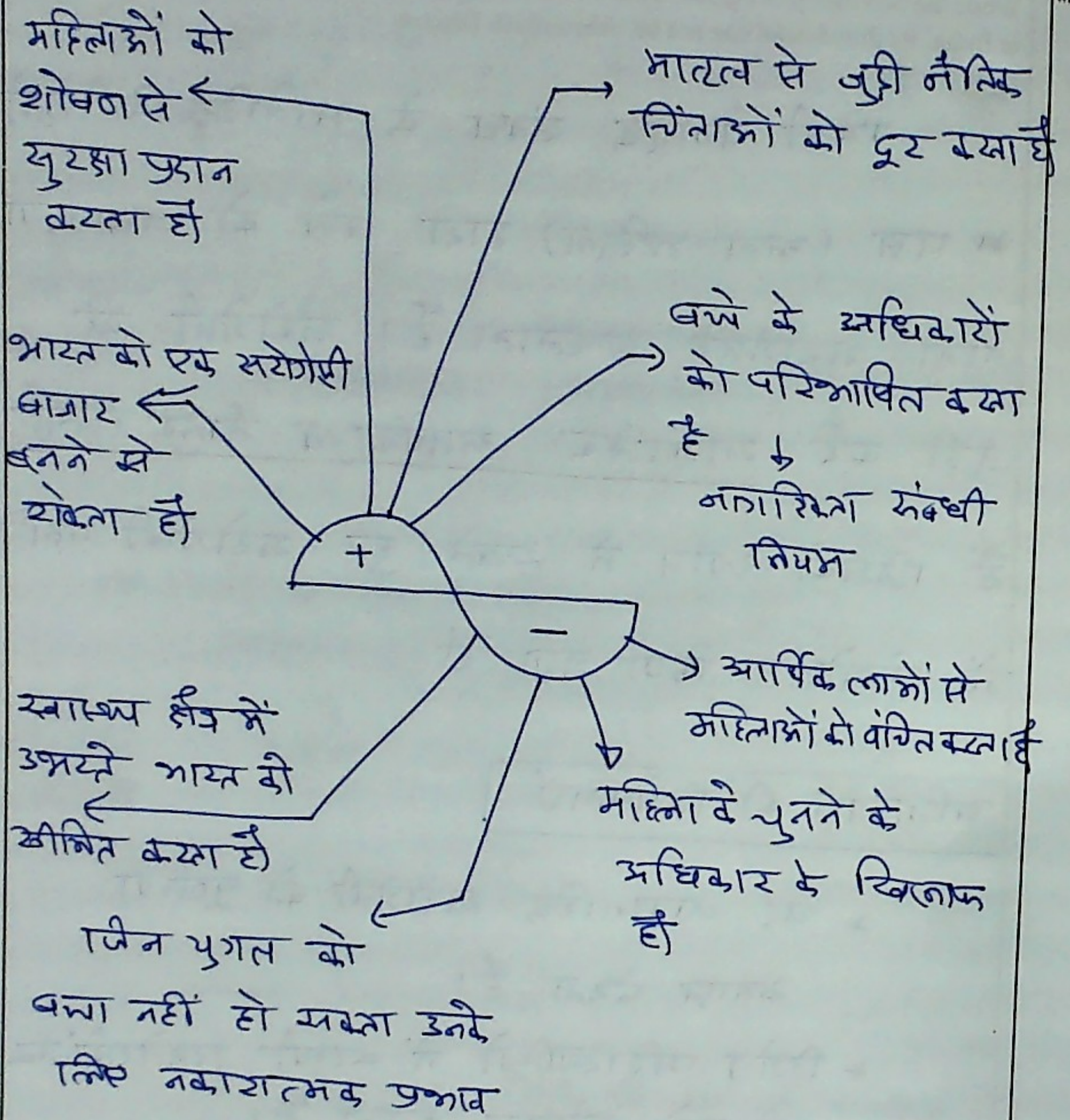
उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

बिना वैवाहिक संबंध के अतिरिक्त किसी तृतीय
* पक्ष (अन्य महिला) द्वारा बच्चे को जन्म दिया
जाना सरोगेसी कहलाता है। सरोगेसी से
जुड़ी कई सामाजिक, आर्थिक व नैतिक चुनौतियाँ
हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरोगेसी अधिनियम
में संशोधन किया गया है

अधिनियम की विशेषताएँ

- * यह व्यवहारिक सरोगेसी को पूर्णतः
अनाप्त करता है।
- * विशेष परिस्थितियों में करीबी रिश्तेदारों तक
ही इसे सीमित करता है।
- * इसे दंडनीय अपराध के रूप में
स्थापित करता है।
- * महिलाओं के खिलाफ शोषण से रोकना
प्रदान करता है।

सुरोगोरी अधिनियम का विश्लेषण



सुरोगोरी एक संवेदनशील मुद्दा है। शोषण के जुड़ी गिनताओं को दूर कर इसके नैतिक पक्षों को संबोधित करने का प्रयास अधिनियम में किया गया है।

उम्मीदवार को
हाशिये में नहीं
चाहिये।
(Candidate must
write on this m

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।
(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario.
Comment.
(150 words) 10

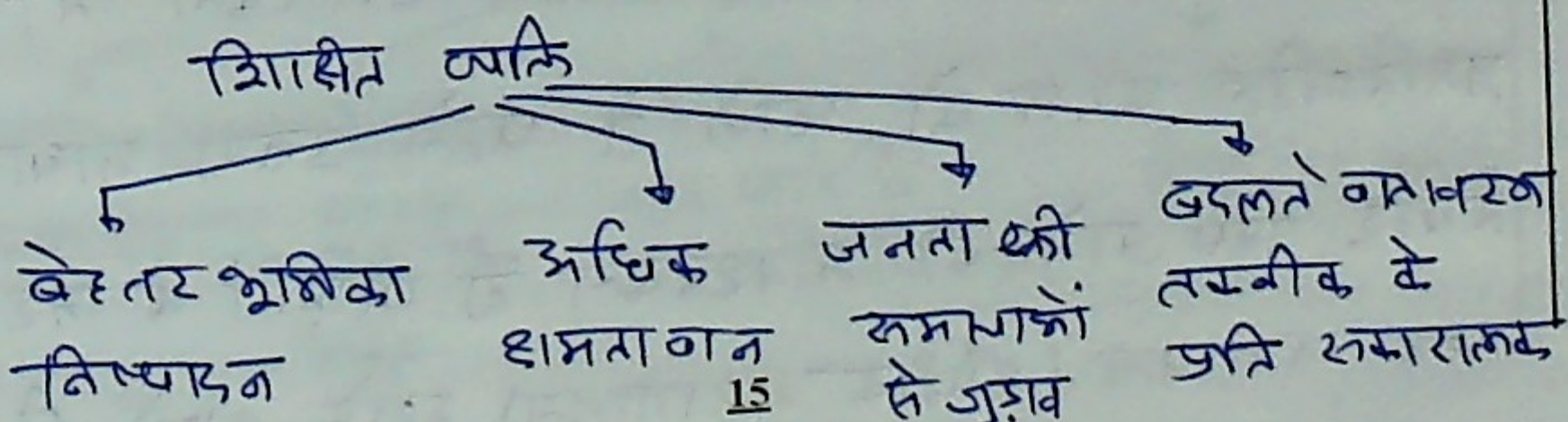
हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज चुनावों में शैक्षिक अनिवार्यता के प्रावधान को खत्म किया गया।

न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एवं प्रगतिशील कदम:-

↳ यह कानून निर्मातकों की अंतिम में शिक्षा शामिल कर उन्हें अधिक प्रगतिशील, संवेदनशील व जागरूक रहने की अपेक्षा करता है

↳ यह प्रतिभाओं को शासन व राजनीति में शामिल होने को प्रेरित करता है

↳ यह इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि



न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकता पुनर्जी के रूप में

* यह संविधान के अनु. 15 के अन्तर्गत के अधिकार के विरुद्ध है

* संविधान में अर्थात् में शामिल नहीं

* जन्मनिधि का निर्धारण शिक्षा से नहीं हो सकता ↓

यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ

↓
एक व्यक्ति एक मत
का अन्तर्गत का सिद्धांत

* पुरानी पीढ़ी के एक बड़े हिस्से में पुनर्जी प्रक्रिया से बाहर रहता है

↓
अनुभव का लाभ जनता को नहीं मिलेगा।

लोकतंत्र अमान्यवादी दृष्टिकोण है। शिक्षा की प्रगतिशील बदन को ज्ञान से पहले उसका आधार तैयार किए जाने की आवश्यकता है विद्वानों के लिए यह अमान्यता (अनु. 16 अमान्यता) इसके लाभों की

www.drishtias.com प्राप्ति में लक्ष्य

Contact: 8750187501, 8448485517

Copyright - Drishti The Vision Foundation

देवी

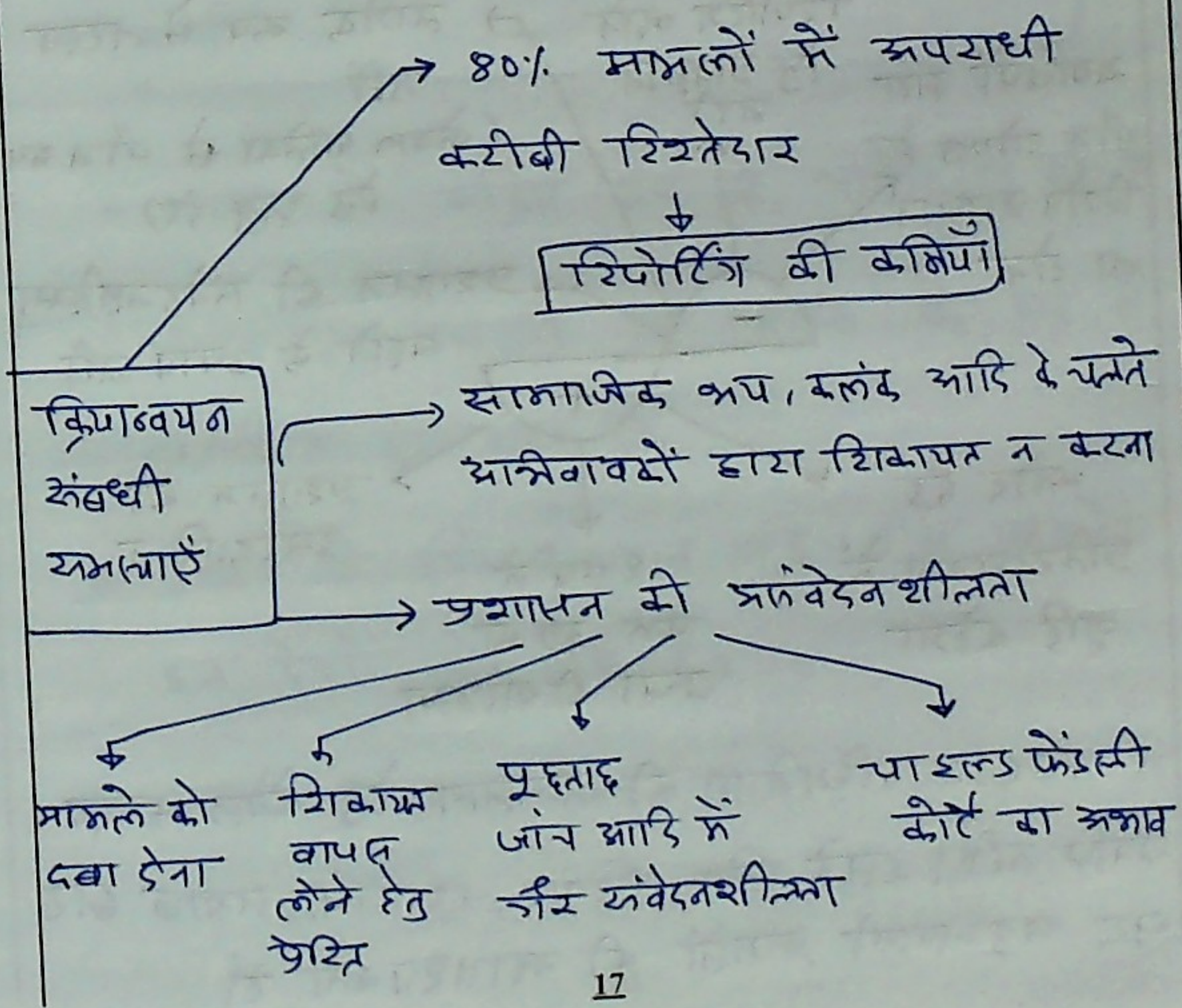
उम्मीदवार को प्र
हाशिये में नहीं
चाहिये।
(Candidate must
write on this ma

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

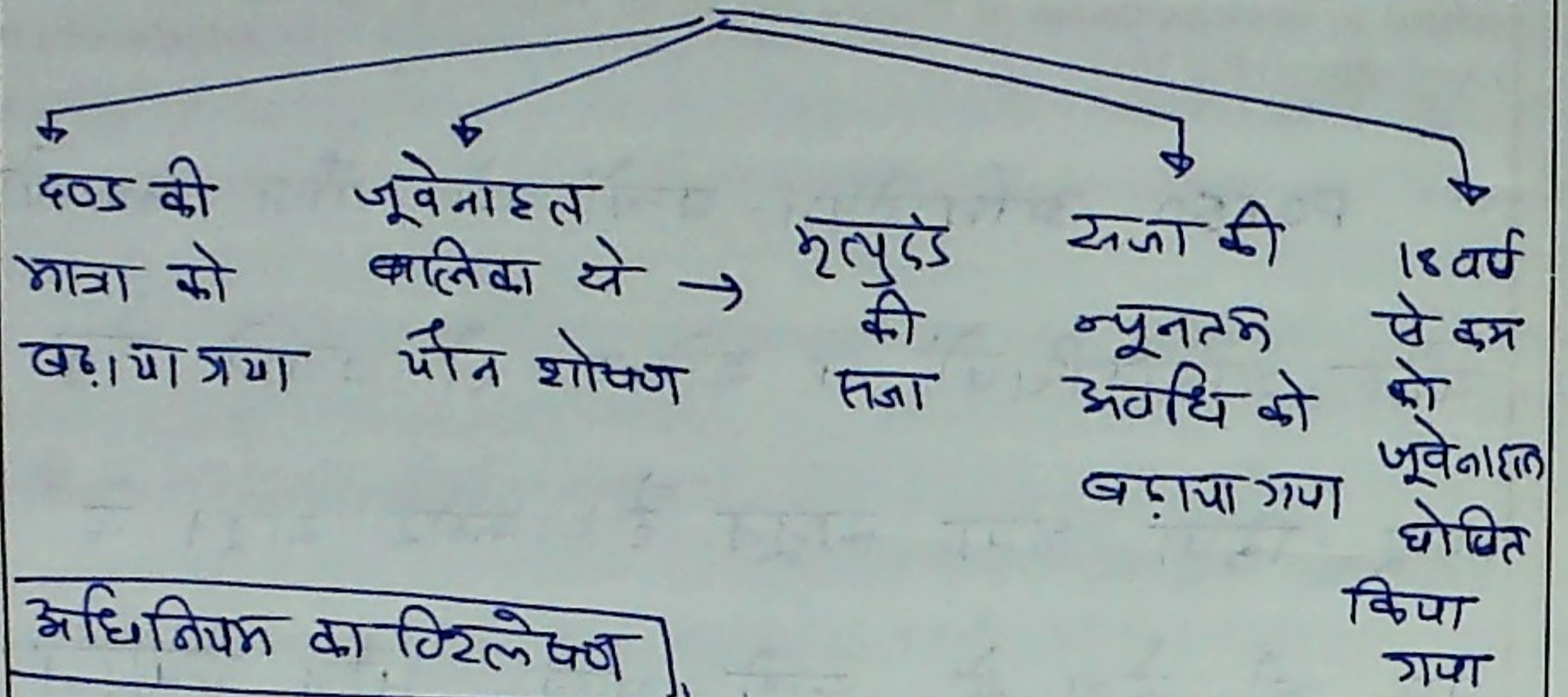
उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

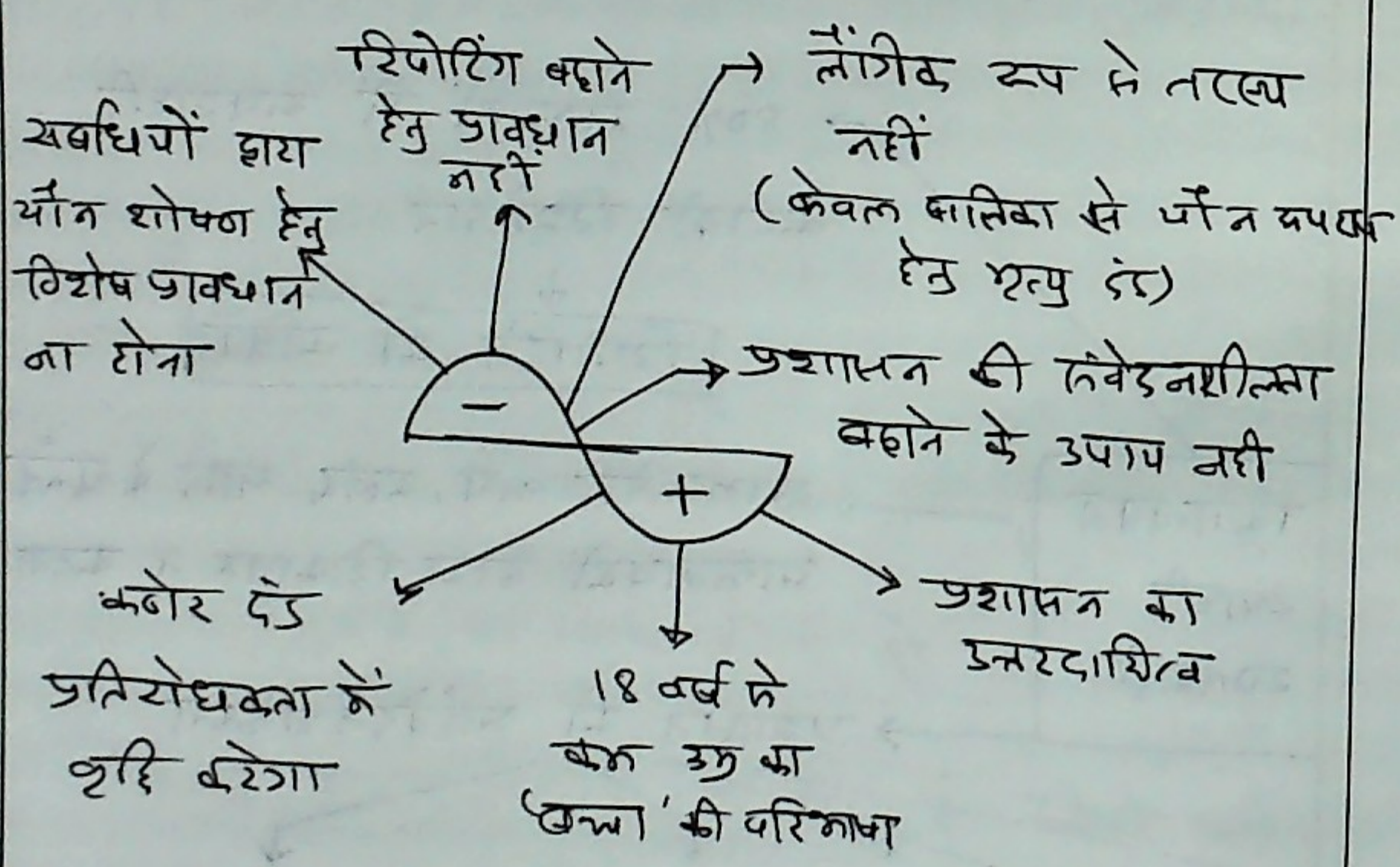
POCSO अधिनियम वनों को घौन अपराधों, घौन गतिविधियों व शोषण से बचाने हेतु लागू किया गया कानून है। कठोर कानून के बाद भी देश के साथे बचे घौन अपराधों का शिकार है।



बच्चों के प्रति जॉन अपराधी से निपटने की खोजी-कठोर बाबूनों की रही है - यथा POCSSO में संशोधन



अधिनियम का विश्लेषण



POCSO अधिनियम की अज्ञातता हेतु केवल काशन उपरि नहीं। इसके लिए परिवार, प्रशासन, समाज और पर बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

इस्लामिक सहयोग संगठन मध्य एशिया,
दक्षिण पश्चिम एशिया के इस्लामिक राष्ट्रों का
एक सहयोग संगठन है जिसमें उज्बेकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आदि शामिल हैं।

भारत की भागीदारी को ऐतिहासिक बताने के
विहितार्थ

* भारत ने सक्रिय रूप से भागीदारी की है

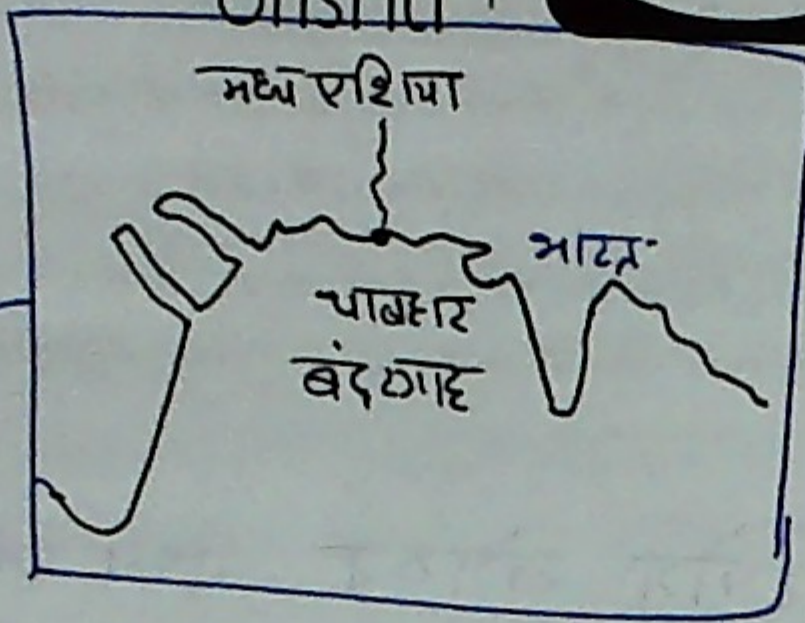
* भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में
स्थापित हो रहा है

* भारत के हिपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग
इन देशों के साथ हैं।

* ऊर्जा, सहायता, तकनीक, नवाचार के क्षेत्र में
इन देशों से सहयोग हो रहा है।



drishti



भारत मध्य एशिया से जुड़ने का प्रयास कर रहा है

↓
बनेबट लेटल एशिया पॉलिसी

भारत बेलिए
भूराजनीति
महत्व

→ हिंद महासागर से मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंचने का लक्ष्य

→ ऊर्जा संधियों पर निर्भरता इस्लामिक देश पेट्रोलियम व गैस के निर्यात

→ TAPI परियोजना की सफलता

→ ताजिकिस्तान में भारतीय सैन्य कड़ा

→ अमेरिका द्वारा ईरान का बहिष्कार संवर्धों में संकुचन हेतु आवश्यक

इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल होकर

भारत ने स्वतंत्र विदेशी नीति का परिचय देते

हुए अपने दिनों को लक्ष्य करने की दिशा में

कदम बढ़ाया है

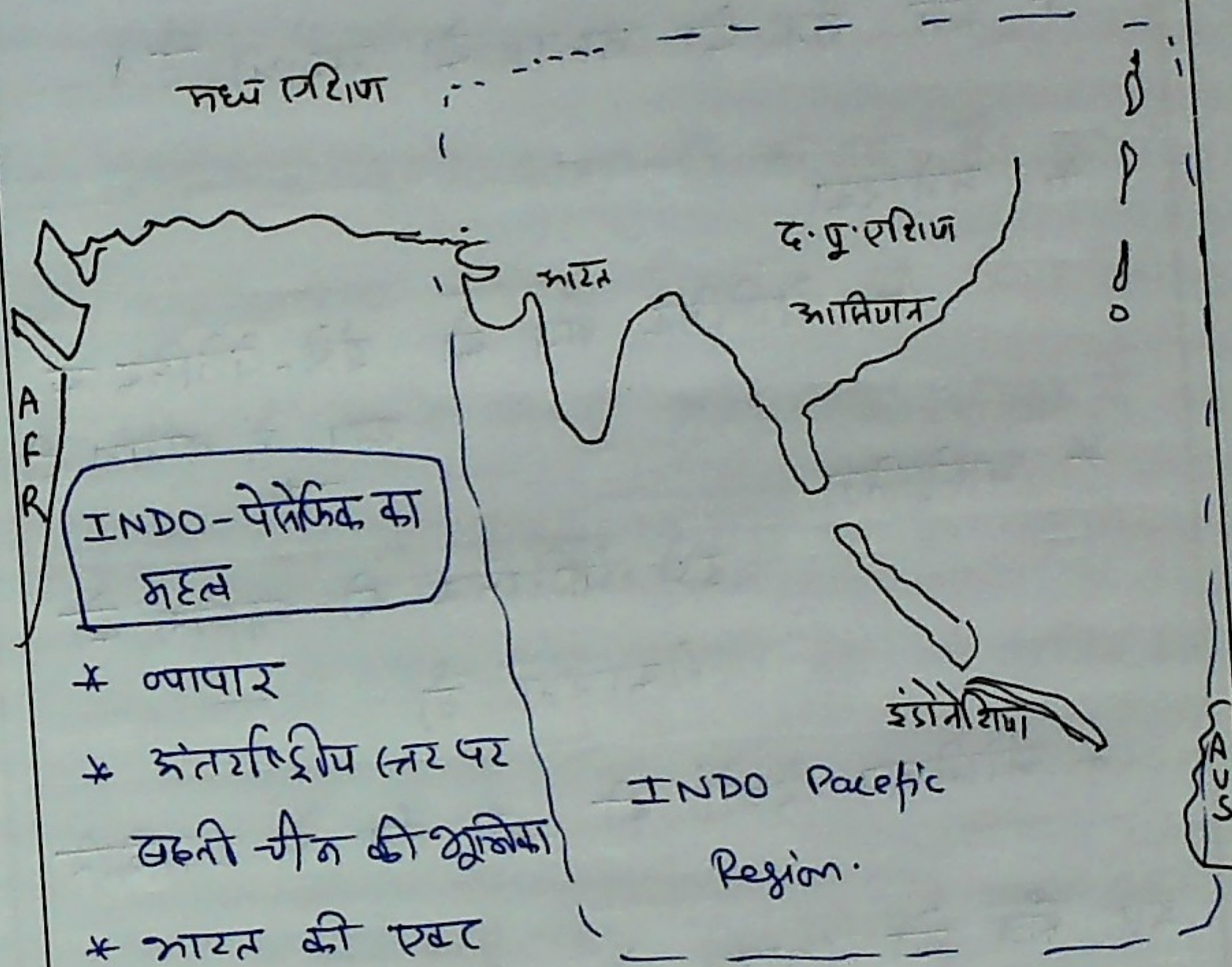
उम्मीदवार को प्र
हसिये में उत्तर
लिखिये।
(Candidate must
write on this page)

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

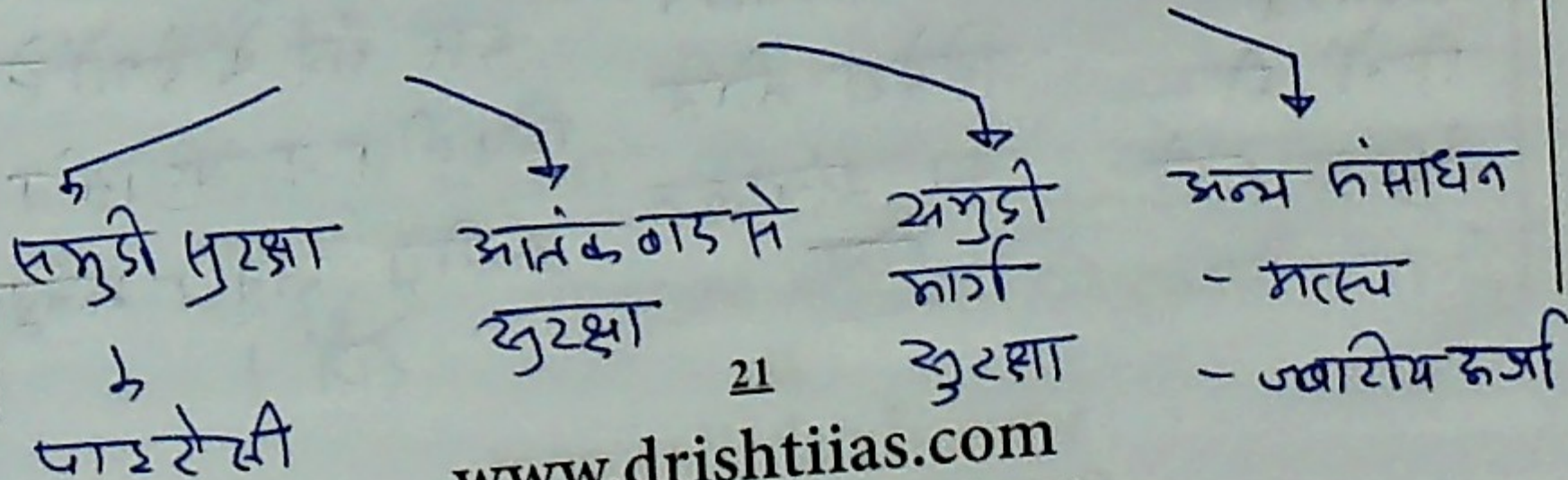
(Candidate must not write on this margin)



- * व्यापार
- * अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चीन की शक्ति
- * भारत की एक्ट ईस्ट पोलिसी को

कारण → ASEAN से जुड़ाव

- * हिंद महासागर में चोली नैटवर्क नाट्यपूर्ण रूप से अर्थ मंत्रालय



* भारत की हिंद महासागर में भू राजनीतिक स्थिति

ने इस क्षेत्र को महत्ता को बढ़ाया है।

* अमेरिका

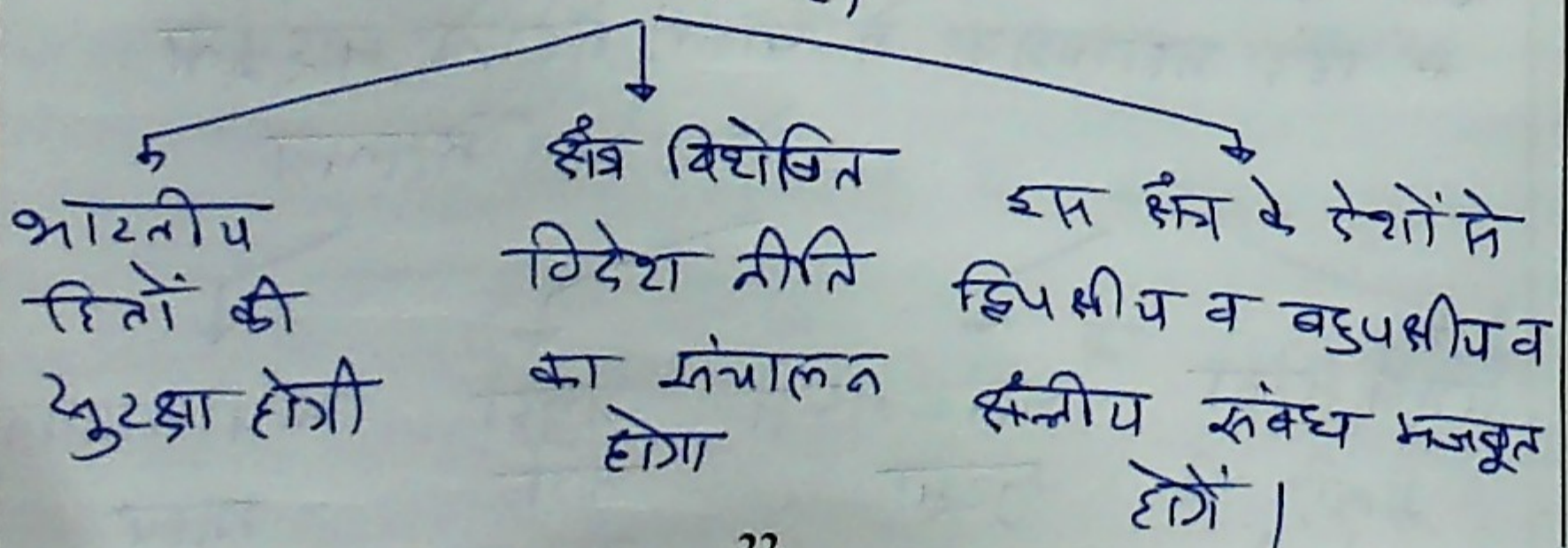
↳ पेट्रोलियम क्षेत्र को इंडो-पैसिफिक के रूप में मान्यता दी है

* आस्ट्रेलिया

- इंडो पैसिफिक की मान्यता को स्वीकारता है

* आसियान देशों की इस क्षेत्र में उपस्थिति

इस क्षेत्र को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। इसी को दृष्टिगत इंडो-पैसिफिक रिक्रान की स्थापना की गयी है



11.

भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

बिना भी लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्र, निष्पक्ष
व बहुपक्षीय चुनावों द्वारा ही संभव है। भारत
में यह दायित्व चुनाव आयोग को दिया गया
है। अनु. 324 के तहत अर्धैच्छात्मिक संस्था के
रूप में यह न केवल चुनावों का आयोजन
करती है बल्कि चुनाव सुधारों को भी प्रेरित करती
है।

चुनाव आयोग द्वारा किए गए सुधार

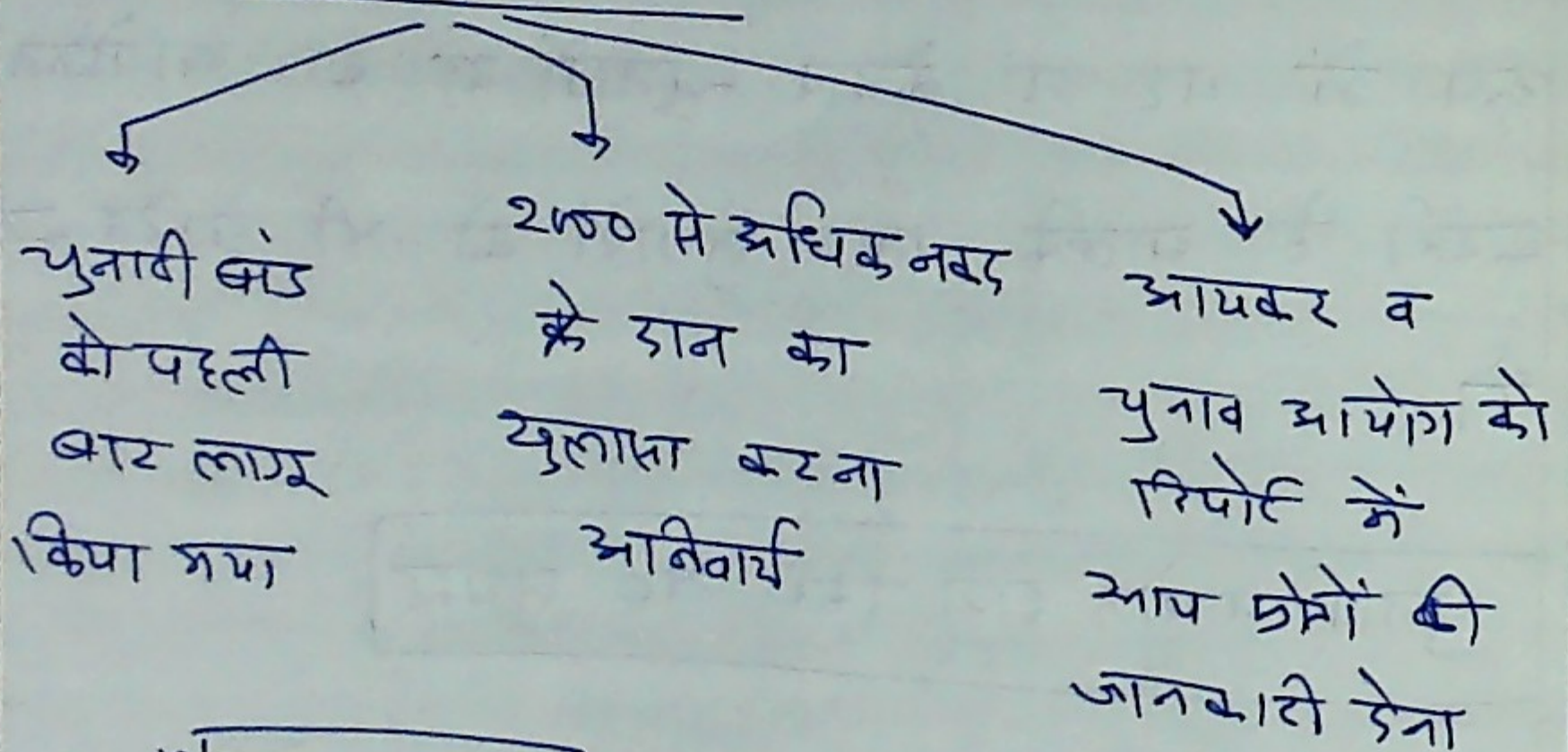
(*) मतदान में VVPAT (वोट वेरिफाइड
पेपर ऑडिट ट्रेल) शामिल की गई ताकि
मतदाता का चुनाव व संस्था में विश्वास
बढ़े।

* सोशल मीडिया पर आचार संहिता का
पालन - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालकों

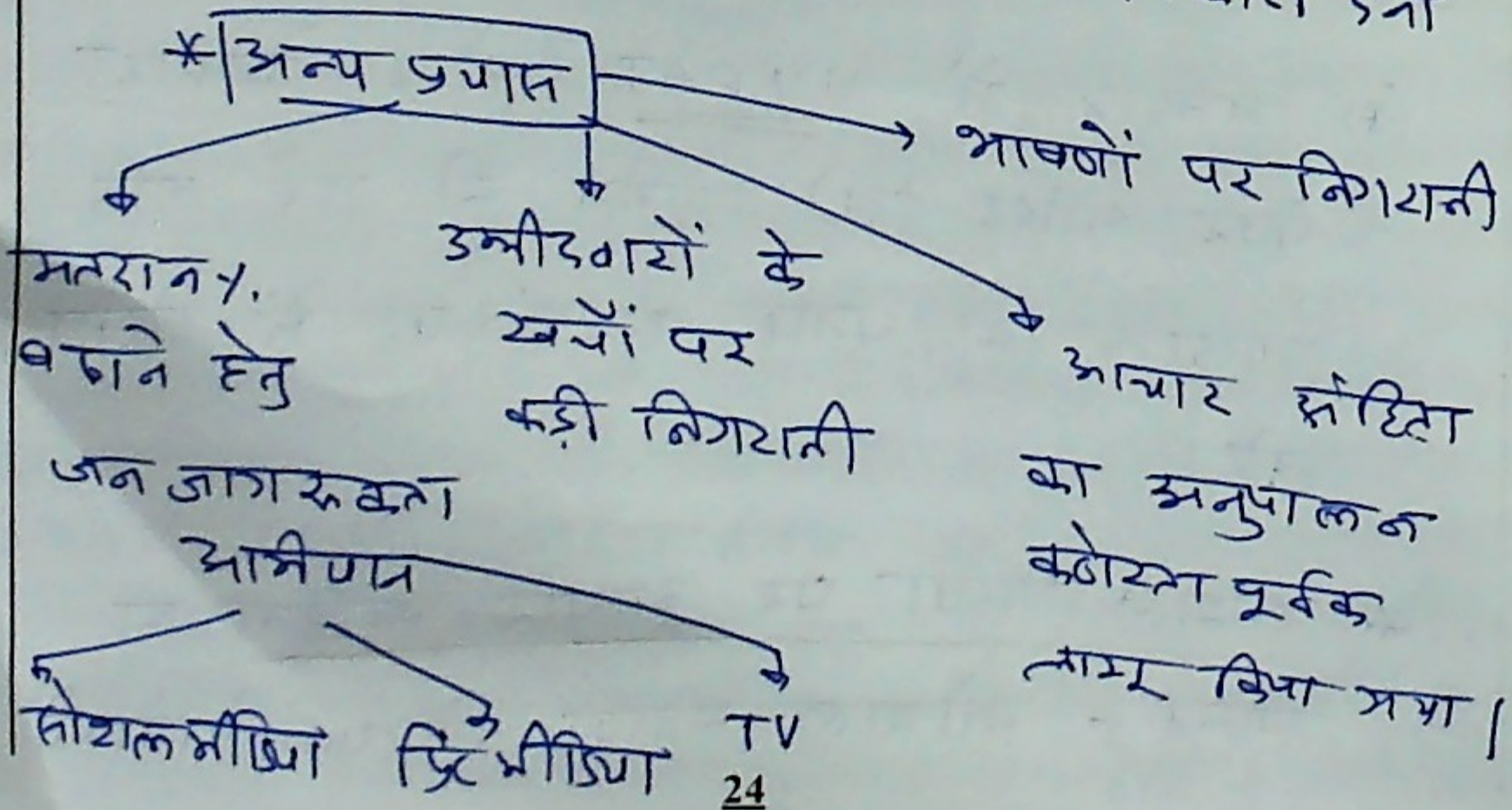
द्वारा बनायी गयी मॉडल आचार संहिता का प्रयोग किया गया।

* चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वंगाल में अल्प पूर्व प्रचार बंद करवाने का निर्णय

* चुनावी विधि दोषण



* अन्य प्रचार



उम्मीदवार को स
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this man)

अबू बी ध्यान
केंद्र के जुड़े

- आचार दंडिता को कानूनन लागू करवाना
- चुनावी खर्च की सीमा के इलाखेव की निखस जंघ
- राजनीति में आप राधीकरण को शेकना
- सोशल मीडिया रिजापनों का विनिपदन व इसे चुनावी खर्च में शामिल किया जाना ।
- वेतन नशीन से जुड़ी आशंकाओं को (EVM) दूर कर जनता में संघा के प्रति विश्वास बहाली ।

- चुनाव आयोग में संस्थागत सुधार, चुनाव आयोग द्वारा सुधार, राजनीतिक फलों द्वारा स्वनिपदन के रिहातों द्वारा स्वस्थ लोकतंत्रिक भारत के रूप में को आकार दिया जा सकता है

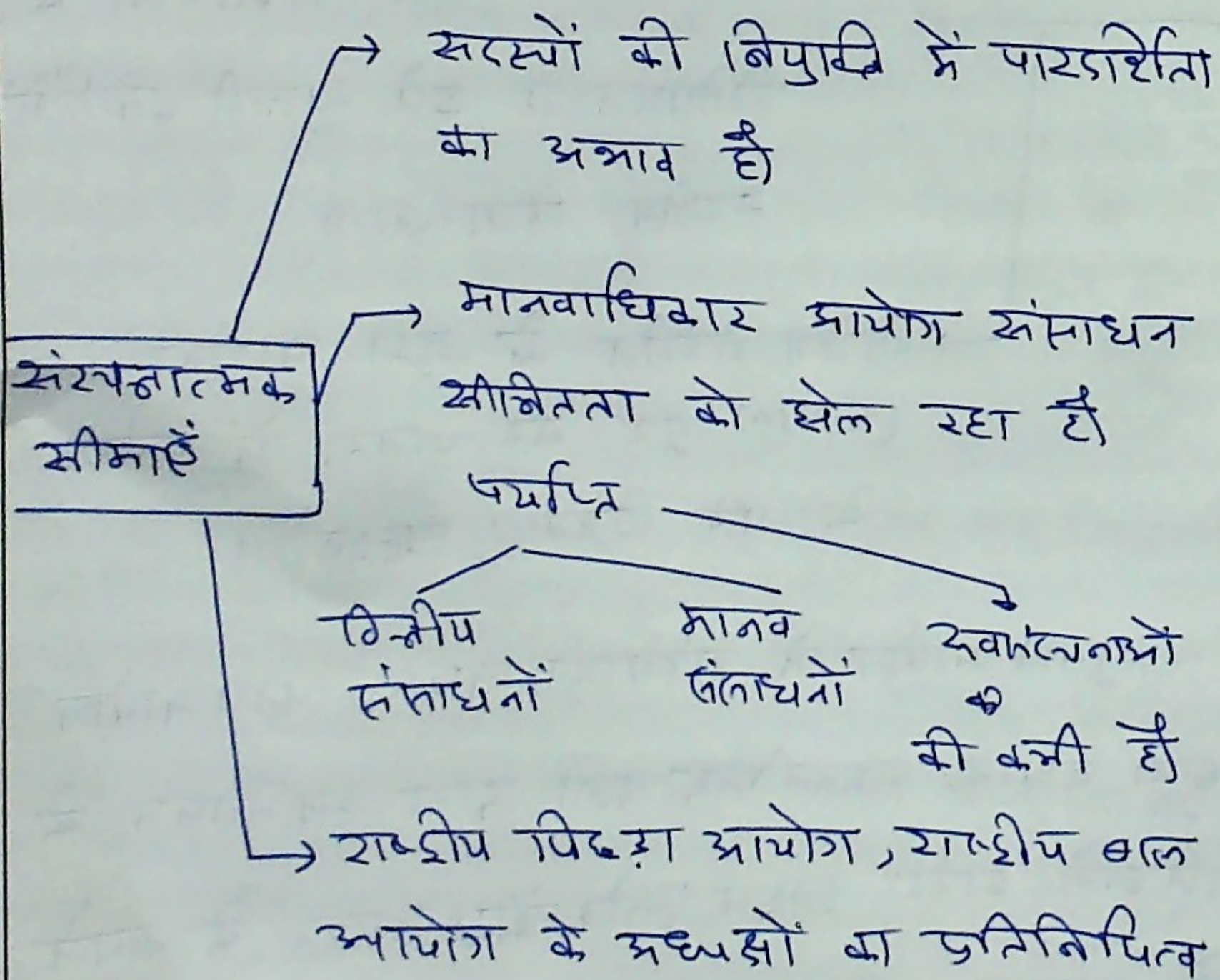
12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिख
चाहिये।

(Candidate must
write on this margin)

अंकुश अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की अनुपलब्धता
में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना
की गयी। यह बहुसदस्यीय वैधानिक निकाय
है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के
तहत स्थापित किया गया है।



**अवधिक
धनाएँ**

→ स्वयं के पास जॉब एजेंसियों का
ना होना

→ बिदेशों की अनुपालना ना होने पर
फंड लगाने की शक्ति का ना होना

→ स्वयं द्वारा दाखिल किये की
शक्तियों का ना होना

→ अवधिक मानवाधिकार धनाएँ AFSPA
क्षेत्रों में जहाँ इनकी शक्तियों का विस्तार
नहीं है

→ 1 वर्ष से पुरानी शिक्षापत्रों का प्रमाण
नहीं ले सकता

सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय

* निपुणता, पदोन्नति सेवा शर्तों में
पर्याप्तता लाने की आवश्यकता है

* मानवाधिकार आयोग की शक्तियों का

विचार किया जाना चाहिए तथा
AFSPA क्षेत्र में भी शक्तियों का विचार
- 1 वर्ष से पुराने मामलों पर
त्व. तंत्र की शक्ति

- * पब्लिक रिलीफ सलाहक उपलब्ध
कराने चाहिए
- * मानव सलाहक की शक्ति करने के
अधिकार दिए जाने चाहिए।
- * आयोग के निर्देशों की तैर अनुपालना की
स्थिति में देश की व्यवस्था होनी चाहिए।
- * बाल आयोग, किशोर आयोग के सदस्यों
का प्रतिनिधित्व

मानवाधिकार आयोग नागरिकों के प्राकृतिक मौलिक
अधिकारों की संरक्षणकारी संस्था है इसके पब्लिक
सुधार कर, शक्तियों प्रदान कर इसे मजबूत
करना जा सकता है

13.

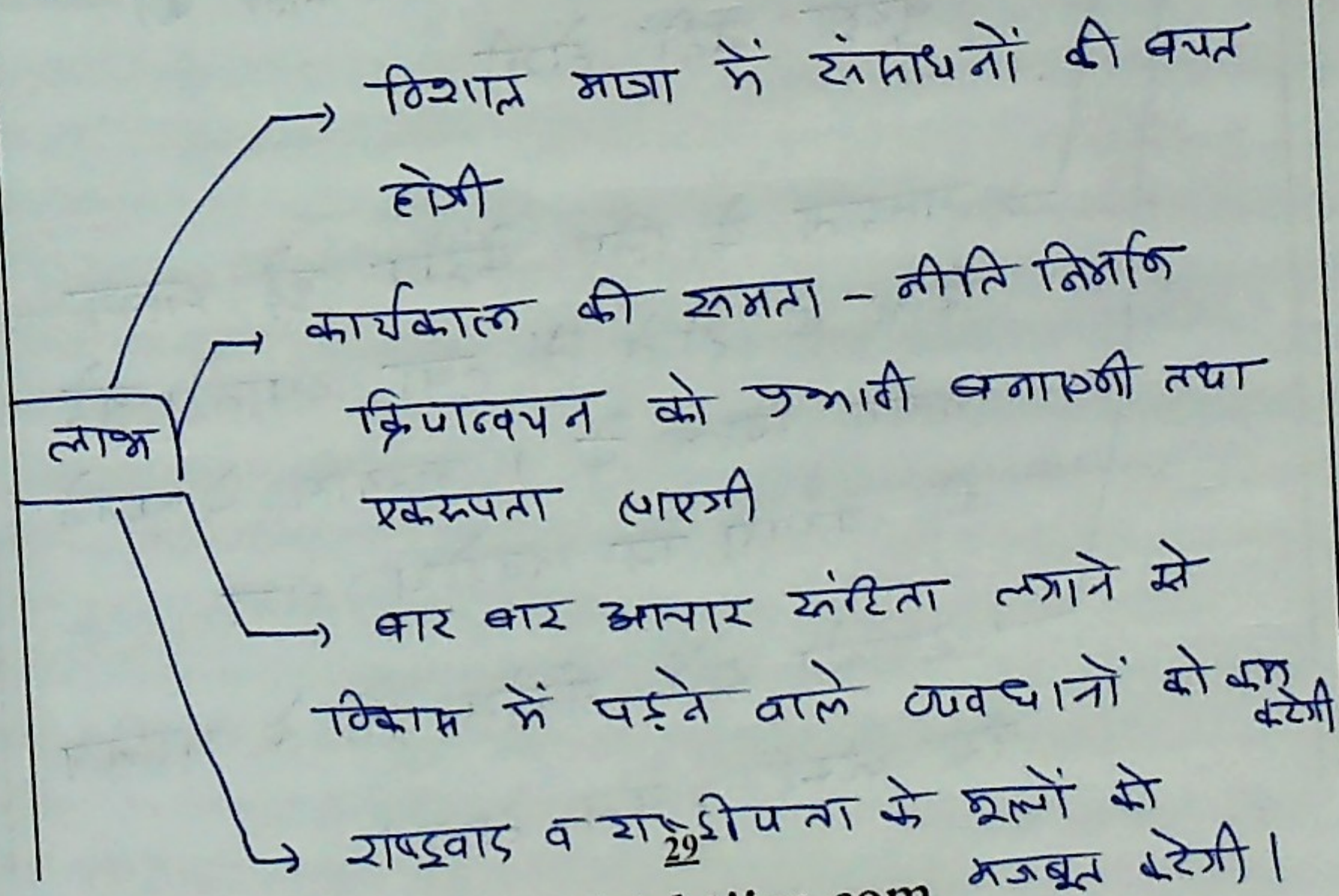
भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत का विशिष्ट विशाल आकार तथा विशाल जनसंख्या चुनावों को पुनर्नी के रूप में प्रस्तुत करती है। भारतीय विदेशीय व्यवस्था केन्द्र स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तर पर चुनाव की व्यवस्था करती है। केन्द्र व राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव। एक राष्ट्र-एक चुनाव की व्यवस्था है।



- केंद्र व राज्य के मध्य सम्बन्ध में
आसानी होगी।

- राज्यों के स्तर पर चुनावी अनिश्चितताओं
को कम करेगी। स्थिरता का लक्ष्य
होगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

चिंतन

→ भारत संघात्मक व्यवस्था है। इसका
प्रभाव राज्य की स्वतंत्र शक्ति के
रूप में आसित्व पर पड़ेगा

→ मध्यवर्ती चुनावों की स्थिति में काली
खरबार के लिए कार्यबल की
सुरक्षा नहीं होगी

→ मतदान के लिए बेटीय मुद्दे अलग
मिलाने के होते हैं तथा स्थानीय मुद्दे
अलग मिलाने के। मतदान के चुनावों
की स्वतंत्रता पर अवरोध होगा

→ स्थानीय दलों, क्षेत्रीय दलों के आसित्व
पर संकट उत्पन्न होगा।

पुनर्निर्वाचन

→ भारत का विशाल आकार पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराने में पुनर्निर्वाचन अत्यन्त जरूरी है

→ एक साथ चुनाव हेतु प्रशासन सुरक्षा हेतु सुरक्षा केंद्र मतदान हेतु EVM, JUPAT जुटाया पुनर्निर्वाचन है

संवैधानिक पुनर्निर्वाचन

* सदन के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति

* वर्तमान कार्यरत विधानसभों के कार्यकाल से जुड़ी पुनर्निर्वाचन

→ भारतीय संविधान के आदर्श - संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने की पुनर्निर्वाचन।

भारतीय राज्यों के से वार्ता कर एक आम सहमति बनाकर ही इतने बड़े निर्णय को लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व भी दिया जाना आवश्यक है

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत में गरीबी के उच्च स्तर (सैकड़ों
खाने के अनुहार 22%) व निम्न आय को
देखें तो स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप
में उभरता है

* एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% स्वास्थ्य खर्च
आफ्नै कॉफ़ पॉकेट खर्च → गरीबी रेखा
के नीचे आ
जाना

> स्वास्थ्य के कारण GDP की 10% की हानि

* GDP का केवल 2% स्वास्थ्य खर्च

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आयुष्मान
भारत योजना की पारिवर्तना की गयी है

योजना की विशेषताएँ

इस योजना के दो धाक हैं

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

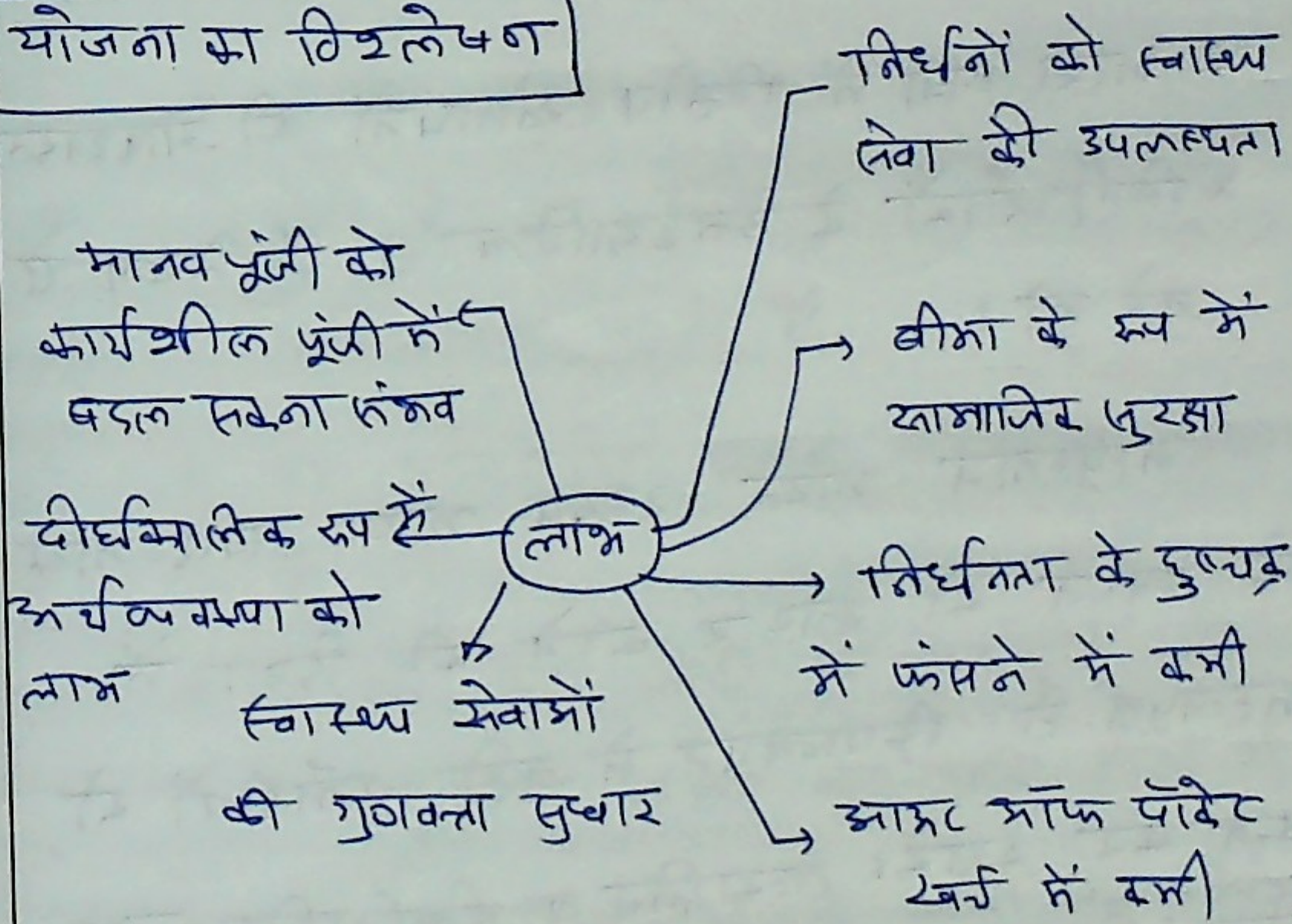
(Candidate must not
write on this margin)

प्राथमिक द्वितीयक
(नगर पर स्वास्थ्य
सेवाओं में सुधार)

स्वास्थ्य बीमा
उपलब्ध कराना
(3 लाख तक का बीमा)

- * देश के 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने की योजना
- * निजी क्षेत्र में भी इलाज करने की सुविधा
- * लाभार्थी की पहचान राज्यों द्वारा।

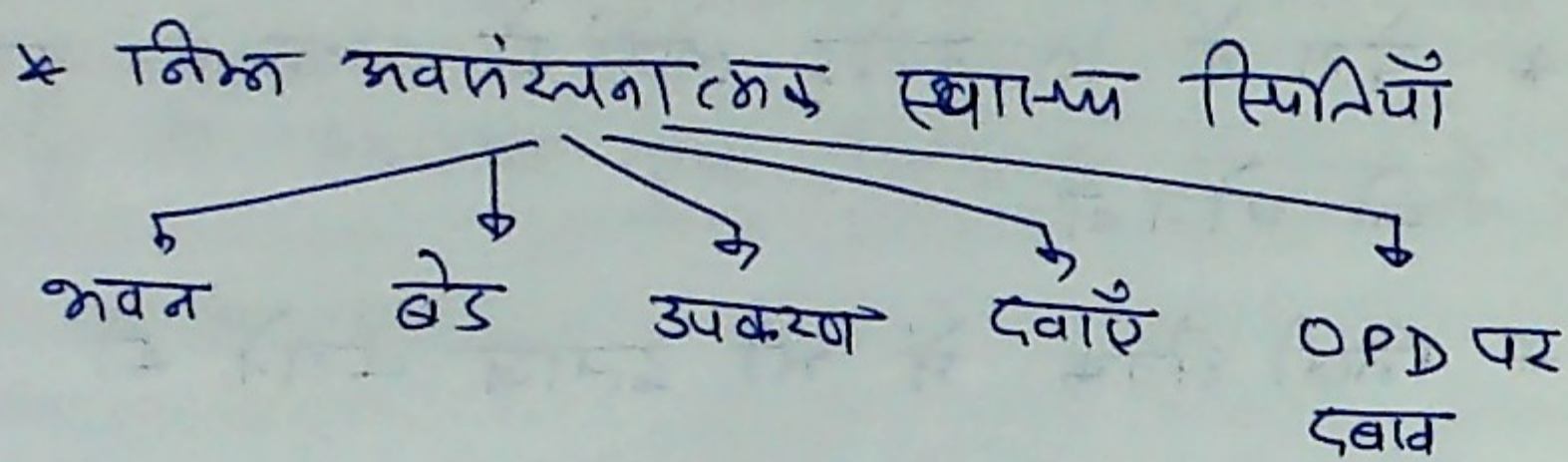
योजना का विश्लेषण



युनैसिफो

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

- * सार्वजनिक स्वास्थ्य सुशासन
- हाल ही में संक्रमण से लोगों की
मृत



- * मानव संसाधन

- * डॉक्टर - 1 लाख जनसंख्या पर केवल
- * नर्स 32

- * भारी मात्रा में विदेशी संसाधनों की आवश्यकता
- * निजी क्षेत्रों के उत्तरदायित्व व नैतिकता से जुड़े जुड़े।

आपुमान भारत स्वस्थ भारत स्वयं भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है रिपान्वपन से जुड़ी युनैसिफो को कर कर इसके तत्कालिक व दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

15.

सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। इस व्यवस्था में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका का निर्माण करते हैं। बहुमत प्राप्त हुए कार्यपालिका का चुनाव कर शासन करते हैं।

संसदीय प्रणाली के गुण

- * सर्वोच्च मंच के रूप में संसद स्थापित होती है जो संविधान के मूल्यों का परिरेक्षण करती है।
- * यह प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
- * सदस्यों, कार्यपालिका के सदस्यों की इतरदायित्व संसद के प्रति होता है।
- * संसद कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण

रखती है

* सना व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित ना होकर एक संस्था द्वारा संचालित होती है

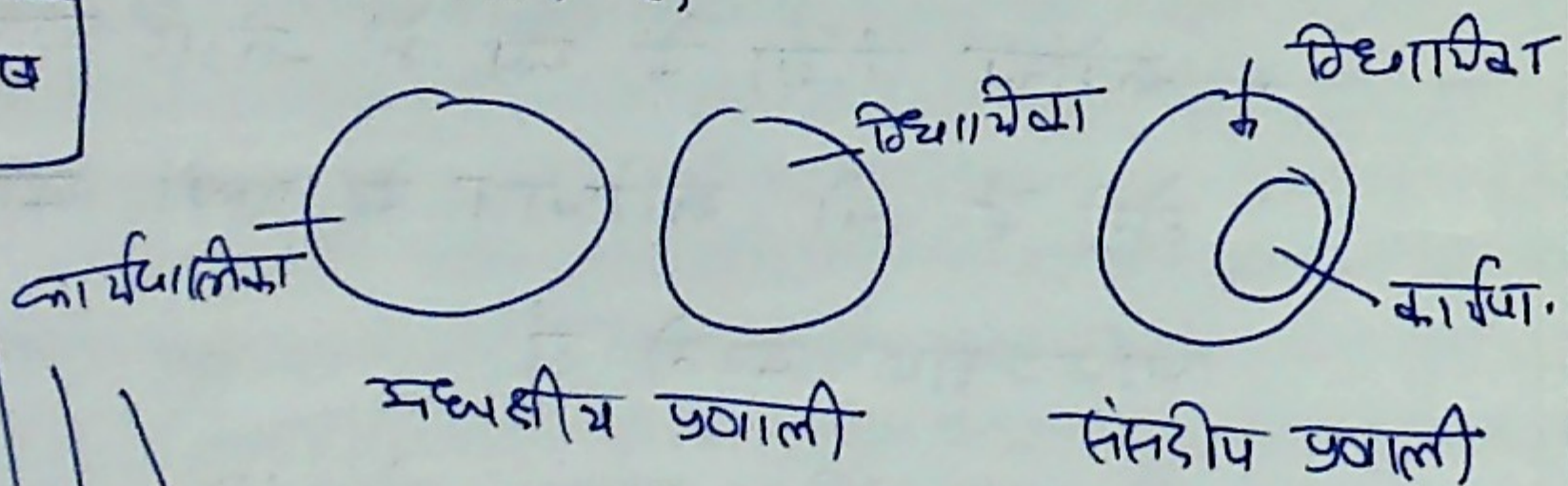
* संसद हर विधि, धर्म, विधान का अंगीकार निश्चय करती है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

कोष

→ यह अध्यात्म प्रणाली के विपरीत है जिनमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है



→ गठबंधन सरकारें आसिद्धा उपलब्ध करती हैं

→ संसद कई महत्वपूर्ण विधियों को स्वतंत्र रूप से लेने से शक्ति रखती है

→ इसके विधियों में देशी होती है

भारत द्वारा संसदीय प्रणाली अपनाए जाने के कारण

* संविधान समितियों ने तत्कालीन परिस्थितियों
व अविषय को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली
को चुना

* तत्कालीन अधिकांश जनसंख्या बिरहारी थी
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जैसी पहलियों को लगभग
कठिन था। संसदीय प्रणाली सरल थी।

* भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों
का विकास संसदीय रूप में ही हुआ था।

* यह व्यवस्था व्यक्ति विशेष के प्रतिनिधित्व
से बनती है।

* भारत जैसी विशिष्टता वाले देश में उपयुक्त

* जन प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष चुनाव सीधे
जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है

संसदीय शासन का स्वरूप शासन को उत्तरदायी
जवाबदेह बनाता है। जन प्रतिनिधि जनता से
सीधे तौर पर जुड़े होते हैं।

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

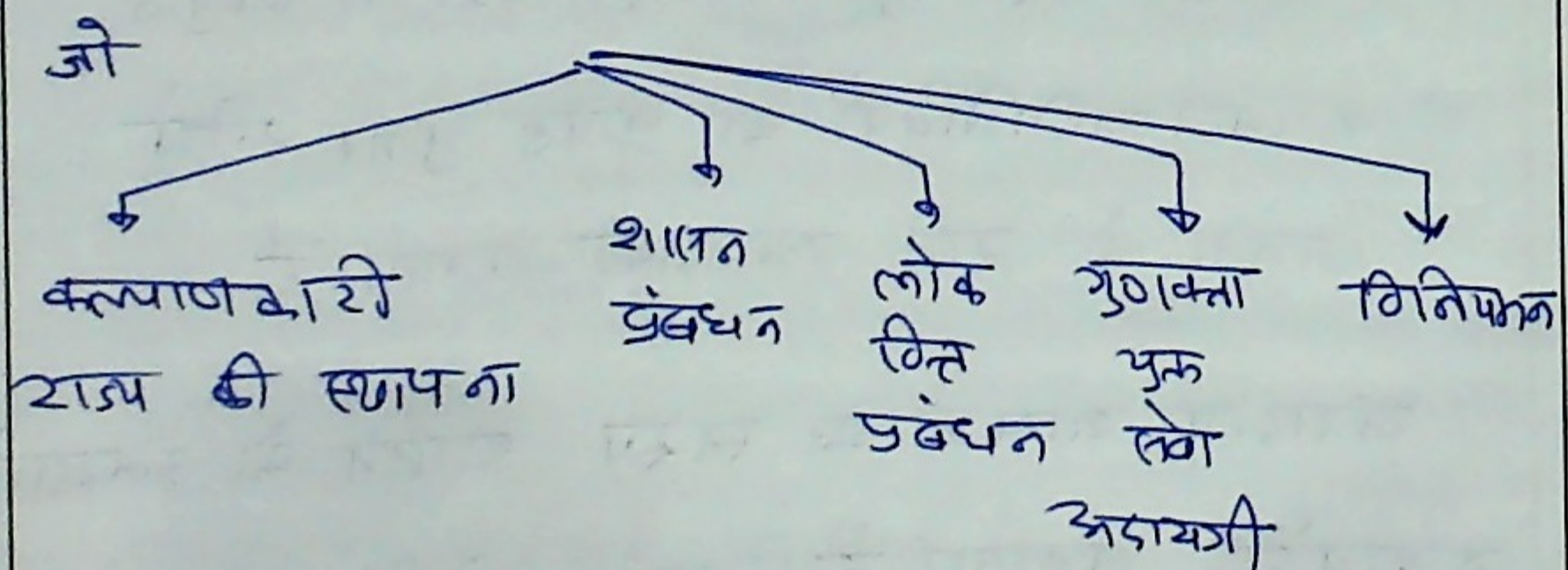
Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

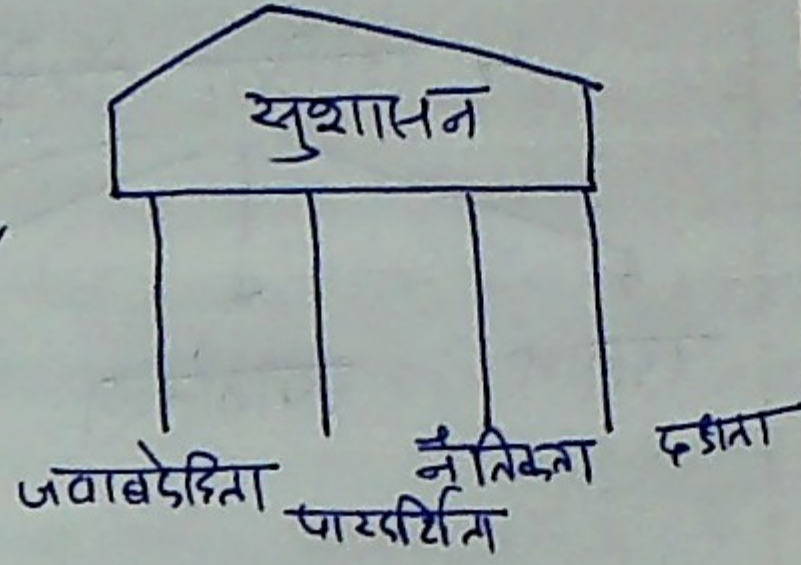
भारत की कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका
(स्थायी) व नौकरशाही (स्थायी) के रूप में
विभाजित है। जिसमें नीति के निर्माण का
उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यपालिका को तथा
नीति क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व नौकरशाही/
निरिक्त लेवकों को दिया गया है।

सैद्धान्तिक तौर पर विभाजन होने के
व्यतिरिक्त वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं



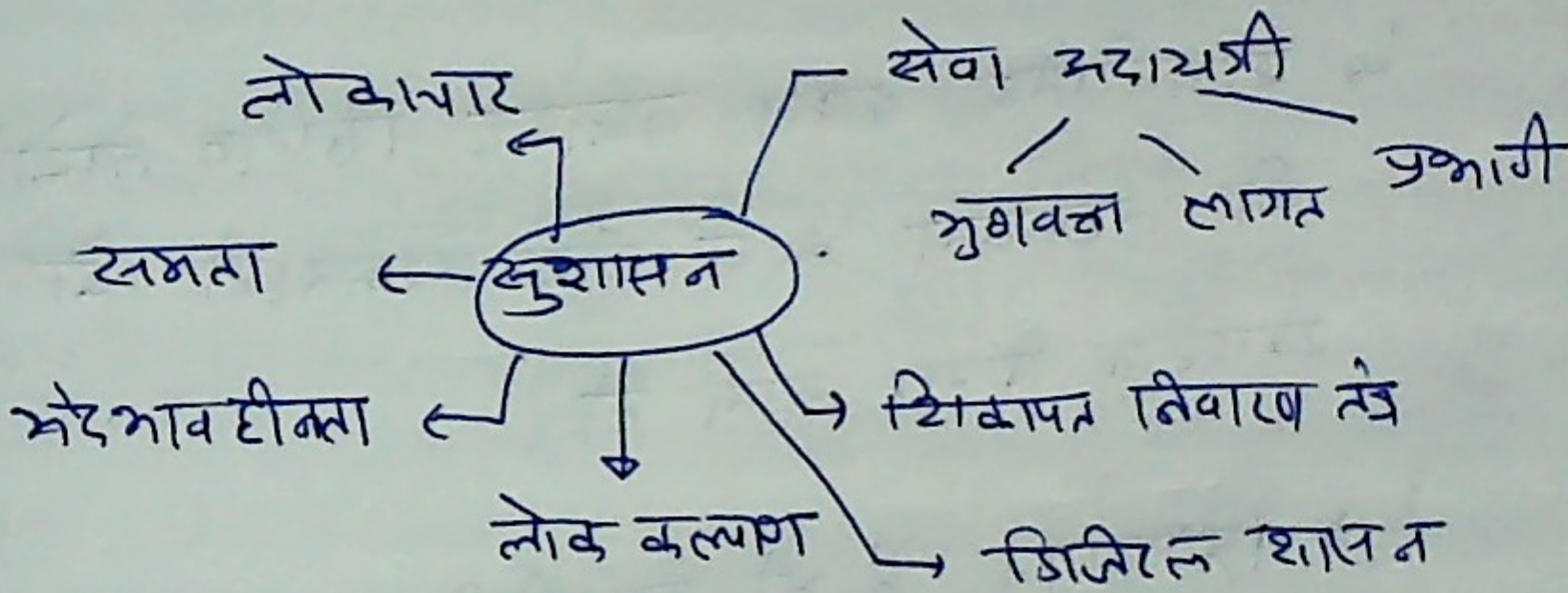
के कार्यों को जनता की मलाई हेतु
सुचारु रूप से करते हैं।

युशासन एक आधुनिक
संकल्पना है जिसमें लोकधार,
समता, न्याय, कर्तव्य और
गुण विद्यमान हैं



युशासन की लक्ष्यता
कार्यक्षमता पर निर्भर है

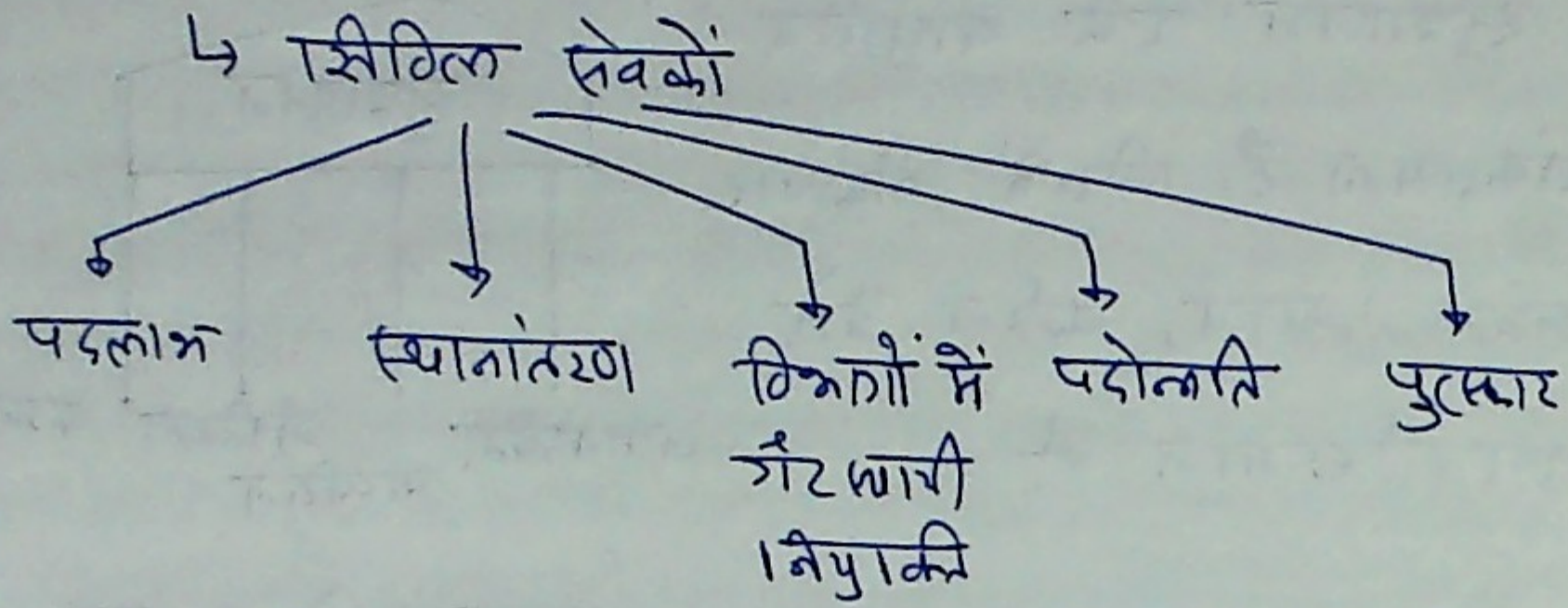
युशासन के चार स्तम्भ



परन्तु दोनों के मध्य कुछ क्षेत्रों में संघर्ष होने
को संभव है

↳ नियुक्ति : आरिब, प्रधान सचिव, ब्रिटीश

आरिब, निदेशक जैसी विपुलियाँ राजनीति
प्रेरित होती हैं।



में राजनीति का एन्तरेष देखने को
मिलता है।

↳ राजनीतिक दबाव बनाकर सिविल सेवाओं
की तस्कणता व व गैर तस्कणकारी को
खारिज किया जाता है।

↳ रिपब्लिकन में भी राजनीतिक एन्तरेष
देखने को मिलता है।

↳ गैर उदत्तपूर्ण कार्यों में संलग्न किया जाना
- UP में कावडियों पर फल बरसाना।

शासन कार्यपालिका द्वारा तंजालित होता है
नौकरशाही परदे के भीतर सरकारी नीतियों का
रिपब्लिकन करती है। दोनों का संरक्षण शासन
के लिए आवश्यक है।

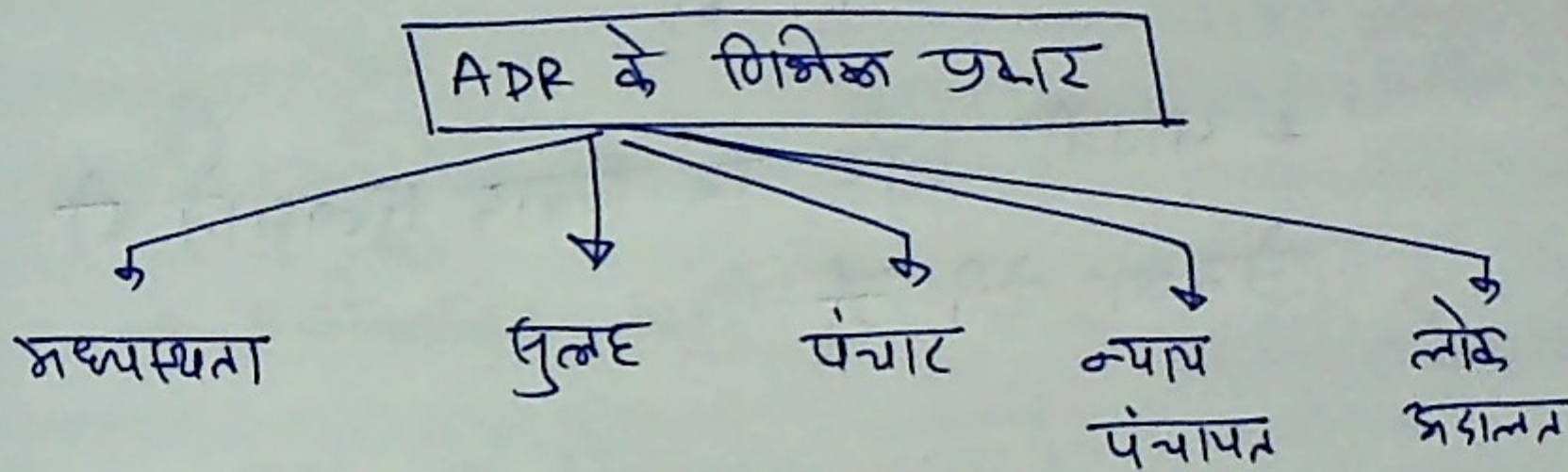
7. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

वैकल्पिक व्यवस्था के विद्वत् के रूप में
अन्य व्यवस्थाओं व संस्थाओं द्वारा व्यापक व
विवाद का समाधान वैकल्पिक विवाद समाधान
कहा जाता है



ADR तंत्र के लाभ

* न्यायपालिका का विद्वत् प्रस्तुत करते
हुए न्यायपालिका के बोझ को कम
करती है - 2 करोड़ से अधिक अपराधों
में सुकटने लगे हैं

* यह लागत प्रभावी है धन की बचत
होती है

* न्याय पालिका की तुलना में तीव्र हैं।
जिससे समय की बचत होती है

* न्यायपालिका की औपचारिकताओं की
पालना आवश्यक नहीं होता

* प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर
कार्य करती हैं

* आपली स्तर पर विवाद सुलझाने की
प्रेरणा देती हैं

ADR के लाभों के बावजूद भारत में इस
तंत्र को कम सफलता मिली है

कारण

* लोगों में जन जागरूकता का अभाव

* लोक अदालतों का आयोजन

समय पर न किया जाता

* कुछ राज्यों द्वारा ही लोक अदालतें

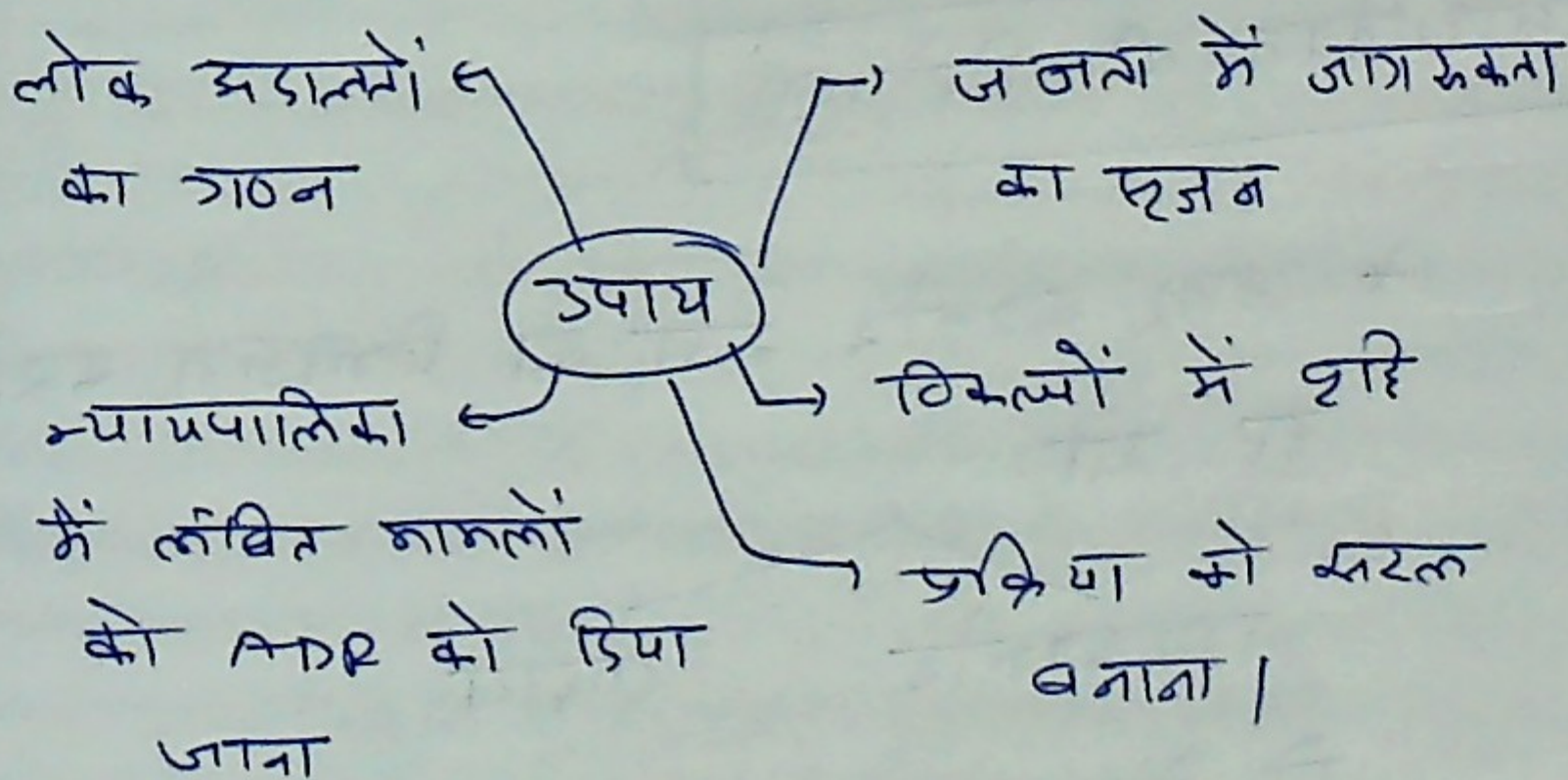
स्थापित की गयी हैं।

* इनके निर्णयों के प्रति अहमति होने पर स्थापनात्मकता के जाने का विषय

* मध्यस्थता तभी संभव जब अतिपूर्व ही ऐसी व्यवस्था हो .

* ADR को न्याय के सीमित क्षेत्रों में ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।

* पारिवारिक मामलों को लोक अदालतों के तहत न निपटाया जाना।



18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

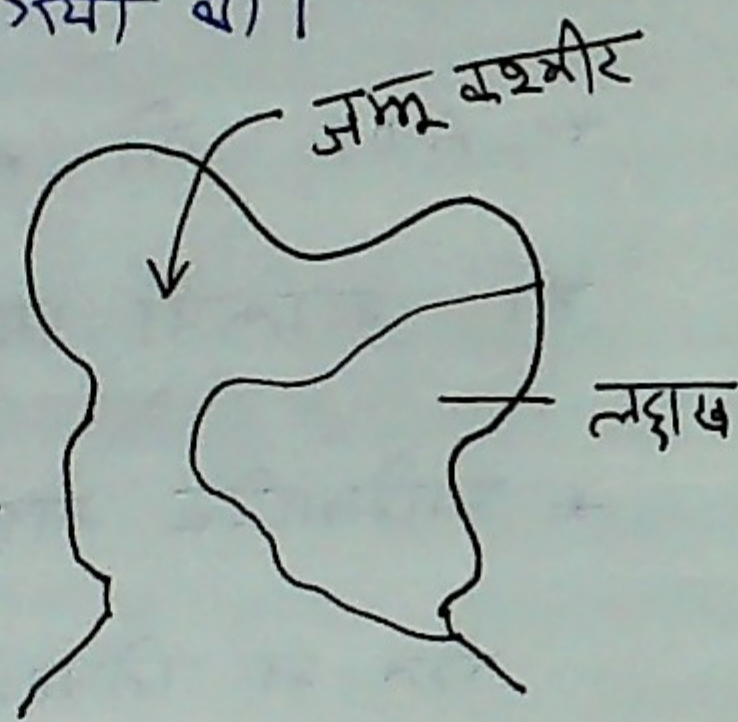
While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने हुए इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी थी।

इन विशेष प्रावधानों की समाप्ति करने हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम - 2019 पारित किया गया



अधिनियम की विशेषताएँ

* जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करते

हुए इसे

जम्मू कश्मीर

लद्दाख

दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में

पुनर्गठित किया गया है

* जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में
विधान सभा व मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल
होगी।

* अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त
किया गया है जिससे अब पूरा भारतीय
संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होगा

↳
इससे पहले जम्मू कश्मीर का अलग
संविधान था।

* देश के किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर
में अंचल, क़स्बे, संपत्ति खरीदने,
व्यवसाय करने, की स्वतंत्रता होगी।

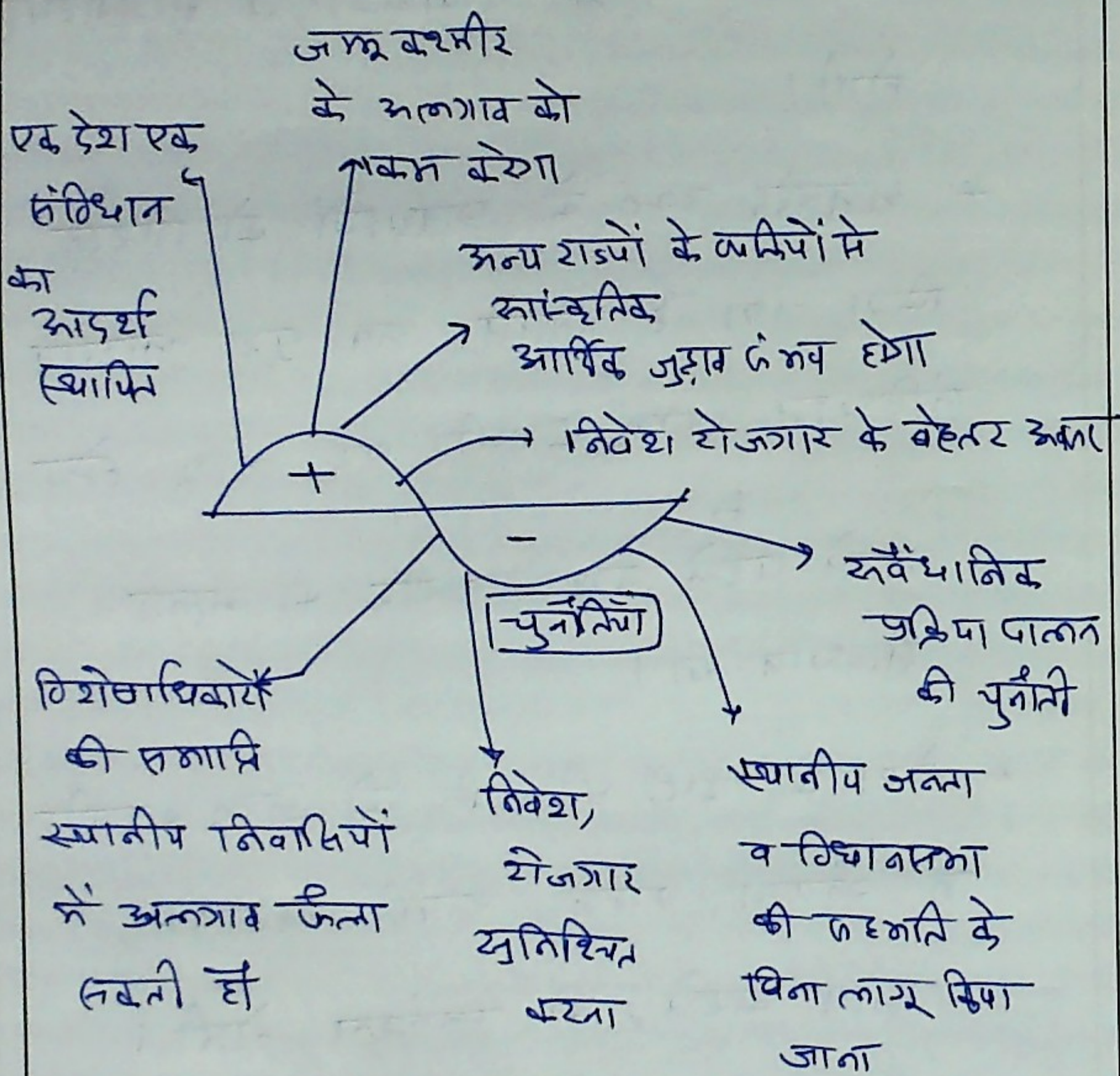
अनुच्छेद 370 समाप्त करने के निर्दिशार्थ

* महिला सभानता स्थापित होगी

- इससे पहले किसी अन्य राज्य के व्यक्ति

ये शादी करने पर संपत्ति के लक्षों से वंचित रखा जाता था

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)



जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन देश के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है स्थानीय निवासियों के संशयों को दूर कर शांति व्यवस्था बहाल की जा सकती है

19.

क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है? (250 शब्द) 15

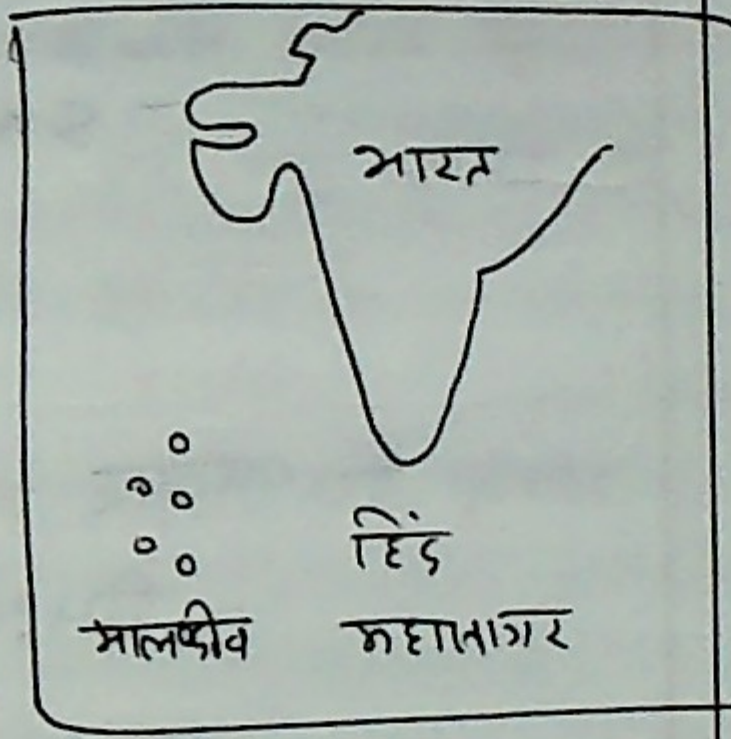
With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत मालदीव संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हाल ही में मालदीव में नई सरकार की स्थापना हुई है भारत के साथ संबंधों में बदलाव देखने को मिले हैं।

भारत मालदीव सहयोग के क्षेत्र



* हिंद महासागर से जुड़े जुड़े-

- सुरक्षा
- व्यापार
- संसाधनों का निष्कर्षण
- मानसून
- मौसम पूर्वानुमान जवाबती में सहयोग

* प्रापदा प्रबंधन

- सुनामी पूर्वनिर्माण हेतु भारत ने
मालदीव में सेंसर लगाए हैं।

* क्षेत्रीय सहयोग

- IORA - हिंद महासागर
रिम एसासिएशन
- SAARC - दक्षिणी एशियाई
सहयोग संगठन

* व्यापार

- द्विपक्षीय व्यापार में एक बड़ी
विस्तारकारी भावना की है।

* निवेश

- भारत एक प्रमुख निवेशकर्ता

* सैन्य

संयुक्त सैन्य अभ्यास
भारत द्वारा सैन्य हेलीकॉप्टर
उपलब्ध कराए गए।

पुर्नोत्थियों
के क्षेत्र

→ चीन की उपस्थिति

भारतीय में वे चीन की उपस्थिति
बढ़ी है वह उसे नष्ट, ड्रेडिट
लाइन लक्ष्यो प्रदान कर रहा है

→ नेतृत्व का उत्तर जगत्

अन्त का लक्ष्य पक्ष भारत के
अहयोग में सब पक्ष भारत को
हस्तक्षेपकारी मानता है

↓
दीर्घकालिक संबंधों पर प्रभाव

→ भारतीय हितों को साधते हुए भारतीय
के हितों की रक्षा - एक संतुलित इष्टि-
कोण की आवश्यकता।

भारत के पड़ोसी देशों में 'बिना प्रदर' की
भूमिका वाला इतिहास उनको नकारात्मक रूप
से प्रभावित करता है पंजीक सिद्धांतों का
अपयोग कर भारतीय के साथ संबंधों में सुधार
बिना जा सकता है

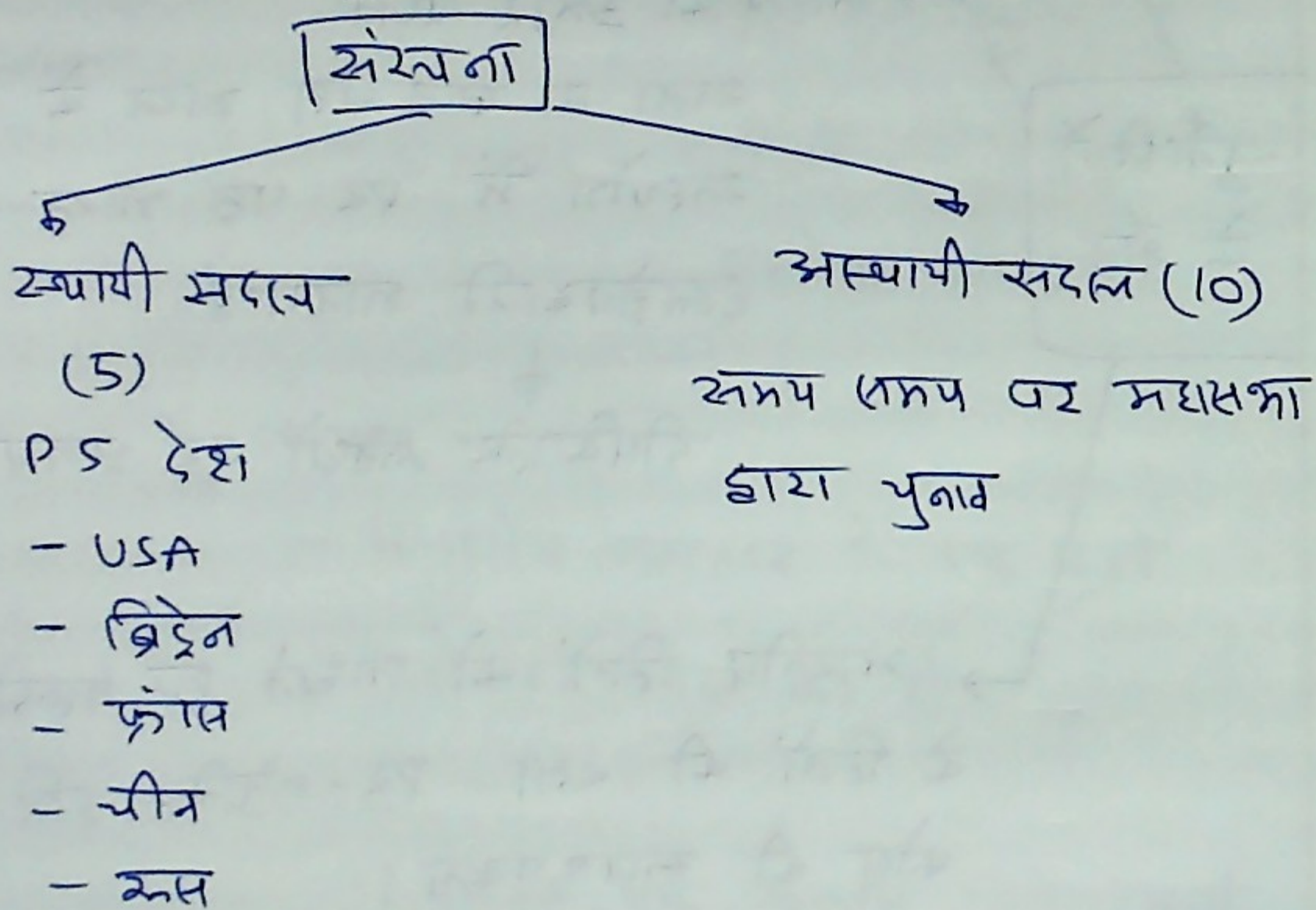
20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं? (250 शब्द) 15

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for delay in bringing out these reforms? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

UNSC संपूर्ण राष्ट्र की सबसे ताकतवर व प्रभावी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका उद्देश्य है।



UNSC का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिज रापा था। बदलते हुई परिस्थितियों में भारत UNSC में सुधारों की मांग कर रहा है।

सुधारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण

* IBSA के माध्यम से भारत इ स्थायी
सदस्यों का विस्तार कर द्वागोलिक
संतुलन की भांग करता है

* भारत शूराजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
रूप से विदले वर्षों में उभरा है
भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए

* भारत कीते आधारित व्यवस्था में सुधार
की भांग करता है कभी कभी स्वयंसेवक
निष्ठियों में कीते शक्ति का दुरुपयोग किया
जाता है

उदा. जम्मू कश्मीर मामलों में चीन द्वारा
कीते किया जाता

* कीते के स्यात पर स्थायी परिषद् का
विस्तार कर बहुमत का नियम लागू
करने का समर्थन करता है

विलंब
के
कारण

→ स्वमत ना बन पाना

- सभी महात्मा के सदर्कों में
सुधारों के प्रति स्वमत नही है

→ सुधार हेतु P5 देशों की सहमति
+
महासभा के 3/4 देशों की सहमति
की आवश्यकता है।

P5 देश अपने विरोधाधिकार छोड़ने
को तैयार नहीं

→ परिषदी देशों द्वारा विरोध
उदा कोफ़ी कल्लब के माध्यम से
पाकिस्तान द्वारा भारत का
अजर्तीना डाय ब्राजील का

→ युद्धाए गए विभिन्न विकल्पों में
ना शामिल होने वाले देशों का विरोध

UNSC का निम्नलिखित तत्कालीन परिस्थितियों में किया

गया था। बदली हुई परिस्थितियों सुधारों को महत्वपूर्ण
बताती है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)